● वर्ष-3
● अंक-296
रायपुर, मंगलवार
22 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› श्रावण मास पर रुद्र के महात्म्य

आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5-7 प्रतिशत और देश की मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत कम होने का अनुमान

अर्थव्यवस्था मजबूत राह पर लेकिन चुनौतियों से निपटना जरूरी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया, जिससे केंद्रीय बजट 2024-25 का खाका तैयार हो गया। वित्त मंत्री मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वृद्धि और वृहद आर्थिक परिदृश्य को लेकर तेजी का रुझान बना हुआ है। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5-7 प्रतिशत और देश की मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है।

भारत का आर्थिक माहौल

भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत और स्थिर स्थिति में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के मामले में लचीलापन बना हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए कोविड के बाद अपनी रिकवरी को मजबूत किया है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, रिकवरी को बनाए रखने के लिए, घरेलू मोर्चे पर मजबूत विकास की जरूरत है। सर्वे के अनुसार व्यापार, निवेश और जलवायु जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों से जुड़े समझौतों तक पहुंचना असाधारण रूप से कठिन हो गया है,। इस दिशा में सुधार की जरूरत है।

विकास दर

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (जीडीपी) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। घरेलू विकास से जुड़े संकेतक अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद स्नङ्क24 में बेहतर रहे हैं। बेहतर बैलेंस शीट से निजी क्षेत्र को मजबूत निवेश मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग की ओर से सामान्य वर्षा पूर्वानुमान और दक्षिण-पश्चिम मानसून के संतोषजनक प्रसार के अनुमान से कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार होने और ग्रामीण मांग बढ़ने संभावना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में तैयार आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसटी और आईबीसी जैसे संरचनात्मक सुधार अपना असर दिखा रहे हैं और उम्मीदों के अनुसार परिणाम दे रहे हैं।

महंगाई

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वैश्विक परेशानियों, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और मानसून की अनियमितताओं के कारण महंगाई का दबाव बढ़ा है। हालांकि, मुद्रास्फीति के दबावों को प्रशासनिक और मौद्रिक नीतियों को अमल में लाकर चतुराई से प्रबंधित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, स्नङ्क23 में 6.7 प्रतिशत के औसत के बाद खुदरा मुद्रास्फीति FY24 में घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई। आर्थिक सर्वे के अनुसार FY24 में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी माल और सेवा दोनों क्षेत्रों में कीमतें घटने से प्रेरित रहीं। FY24 में सेवा क्षेत्र की कोर महंगाई नौ साल के निचले स्तर पर आ गई वहीं। वहीं माल की कोर महंगाई भी घटकर चार साल के निचले स्तर पर आ गई। खाद्य मुद्रास्फीति पिछले दो वर्षों से वैश्विक चिंता का विषय रही है। भारत में कृषि क्षेत्र को चरम मौसम की घटनाओं, जलाशयों की कमी और फसल क्षति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ीं। सर्वेक्षण के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में 6.6 प्रतिशत थी और वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई। आरबीआई ने मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष 25 में 4.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 26 में 4.1 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान जताया है। मानसून सामान्य रहा और कोई बाहरी या नीतिगत झटके नहीं लगा तो यह संभव है। इसी तरह, आईएमएफ ने भारत के लिए 2024 में मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत और 2025 में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

भारत की राजकोषीय स्थिति

आर्थिक सर्वे के अनुसार सरकार के राजकोषीय संतुलन में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, प्रक्रियात्मक सुधारों, खर्चे में संयम बरतने और बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण भारत को राजकोषीय मार्चे पर अच्छा संतुलन हासिल करने में मदद मिली है। वस्तुओं की वैश्विक मांग में कमी से निर्यात पर दबाव पड़ा है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात ने इसे काफी हद तक संतुलित किया है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 24 के दौरान चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत रहा, जो FY23 के जीडीपी के 2.0 प्रतिशत के घाटे से बेहतर है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राजकोषीय घाटा और कर्ज का बोझ बढ़ने की वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत भारत राजकोषीय मजबूती की राह पर बना हुआ है। 2023 में अनुकूल राजकोषीय प्रदर्शन, भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता का आधार बना। महालेखा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत हो गया है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत बना हुआ है।

हम विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे: पीएम

लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को उजागर करता है। पीएम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण हमारी सरकार की ओर से लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को रेखांकित करता है। पीएम ने एक्स पर कहा कि इस आर्थिक सर्वेक्षण से देश में आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान होती है। पीएम ने आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को रेखांकित करता है और सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी प्रदर्शित करता है।

किरंदुल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का जल्द मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व अमले द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे किया जा रहा है। कलेक्टर दंतेवाड़ा ने राजस्व अमले को मकानों, पालतु पशुओं आदि के नुकसान के संबंध में जल्द सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा किरंदुल में जगह-जगह बारिश से हुए जल जमाव को कोपर टेउक्टर मशीन के द्वारा रोड की साफ सफाई की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों कांवड़िए हैरान, योगी करेंगे बड़ा खेल?

नई दिल्ली। सावन के पहले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने लाखों कांवड़ियों को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा पारित निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। योगी का ये फैसला इसलिए आया था क्योंकि कई दुकान, ढाबे और होटल मिले जिनके नाम तो हिंदू थे लेकिन मालिक मुसलमान। ऐसे में सीएम योगी ने आदेश दिया कि सही नाम के साथ ही दुकान चलानी होगी। इस सख्ती के बाद कई दुकानों ने अपने असली नाम लगाए। योगी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो गए, बुद्धिजीवि बौखला गए। योगी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें कांवरिया मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों सिर्फ खाने का प्रकार बताने की जरूरत है। यानी शाकाहारी है या मांसाहारी वो बताने की जरूरत होगी। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। यानी फिलहाल असली पहचान और नाम छुपाकर दुकान और ठेला चलाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा दावा किया गया है कि सीएम योगी एक बड़ा खेल करने वाले हैं। अगर योगी ने वो दांव चल दिया तो पूरा मामला पलट जाएगा। आपको याद दिला दे कि 2020 में सीएए कानून के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे थे। दंगाई पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे थे। तब योगी ने दंगाईयों से नुकसान की भरपाई का आदेश दिया था। दंगाई की फोटो चौराहे पर लगाई जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आपने किस कानून के तहत ऐसा किया। लेकिन योगी ने कुछ ही दिनों में ऐसा कानून बना भी दिया। जिसके बाद दंगाईयों की तस्वीरें फिर चौराहे पर लगा दी गई।

फैसले का विपक्ष ने किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट को फैसले का विपक्ष ने दिल खोलकर स्वागत किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे का स्वागत करते हैं। यह असंवैधानिक था और पूरे विपक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री अपने मुख्यमंत्रियों को उनके राज धर्म के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें इन असंवैधानिक कदमों में शामिल होने से रोकेंगे।

प्रमुख समाचार

बंगाल में विधायकों का शपथ ग्रहण असंवैधानिक

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल के दो विधायक सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार का शपथ-विवाद खत्म नहीं हुआ है। दोनों विधायकों को लिखे पत्र में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि उन्होंने शपथ असंवैधानिक तरीके से ली है। जानकारी के मुताबिक, पत्र में सायंतिका और रेयात के विधानसभा चुनाव में भाग लेने पर संभावित सजा का भी जिक्र किया गया है। राज्यपाल बोस ने कुल 37 मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर को राज्यपाल को शपथ दिलाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। पत्र में, बोस ने सायंतिका-रेयात से यह बताने के लिए कहा है कि उनकी शपथ किसने पढ़ी। उन्होंने यह भी बताया कि अगर उपसभापति उनके निर्देशानुसार शपथ नहीं पढ़ते हैं तो यह असंवैधानिक है। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में दोनों विधायकों पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है, इसकी भी जानकारी पत्र में दी गई है। सयंतिका ने कहा कि वह इस मामले की जानकारी स्पीकर को देंगी। उपचुनाव में बरहनगर से जीतने वाली सायंतिका और भागबंगोला निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले रेयात को 5 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने शपथ दिलाई थी।

तीन साल में मंत्रियों ने दिए 913 आश्वासन, इनमें 583 लागू

नई दिल्ली। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने बताया कि नीतियों में बदलाव और संशोधन की आवश्यकता के कारण कुछ आश्वासनों को लागू नहीं किया जा सका है। उन्होंने आगे बताया कि इन आश्वासनों को आश्वासन की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना जरूरी है। हालांकि, कुछ आश्वासनों को समय पर लागू नहीं किया जा सका और आश्वासन समिति से समय-सीमा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक संसद के 253वें सत्र में कुल 120, 254वें सत्र में 105, 255वें सत्र में 25, 256वें सत्र में 221, 257वें सत्र में 70, 258वें सत्र में 95, 259वें सत्र में 118, 260वें सत्र में 99, 261वें विशेष सत्र में शून्य आश्वासन और 262वें सत्र में 60 आश्वासन दिए गए थे। वहीं वाईएसआरसीपी सांसद रयागा कृष्णैया की तरफ से पूछे गए सवालों का उत्तर देते हुए मंत्री एल. मुरुगन ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस) नामक एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है और सभी मंत्रालयों को आईडी और पासवर्ड भी दिए गए हैं।

बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र का जवाब

नई दिल्ली। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को आज केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। सरकार ने आज संसद में साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने संसद में इसका लिखित जवाब दिया है। योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को प्रदान किया गया था, जिनमें कई विशेषताएं थीं जिन पर विशेष विचार की आवश्यकता थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने विचार किया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला बिहार के लिए नहीं बना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग बहुत पुरानी रही है।

आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर भीषण आग से बड़ा नुकसान

मुंबई। भारतीय नौसेना की जानकारी के अनुसार, बहु-भूमिका वाले युद्धपोत जहाज ब्रह्मपुत्र पर 21 जुलाई की शाम को उस वक्त आग लग गई थी, जब उसकी मरम्मत की जा रही थी। नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई और बंदरगाह में मौजूद अन्य जहाजों के अग्निशमन कर्मियों की सहायता से जहाज के चालक दल ने 22 जुलाई की सुबह तक आग पर काबू पा लिया था। इसके अलावा, आग लगने के बाद जोखिम के आकलन के लिए सैनिटाइजेशन जांच समेत कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर लगी आग की घटना में, युद्धपोत एक तरफ झुक गया है और तमाम कोशिशों के बावजूद, जहाज को सीधा नहीं किया जा सका है। फिलहाल जहाज एक तरफ टिका हुआ है। वहीं इस हादसे में एक जूनियर नाविक को छोड़कर सभी कर्मियों को बचा लिया गया है। वहीं जूनियर नाविक की तलाश की जा रही है। जबकि इस दुर्घटना की जांच के लिए भारतीय नौसेना ने जांच का आदेश दिया है। श्रेणी का पहला निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है। इसे अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

पूर्व राजदूत तरणजीत संधू ने ट्रंप को बताया मजबूत

नई दिल्ली। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी दुनिया का ध्यान है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन अपनी दावेदारी से पीछे हट जाते हैं और इस तरह हार-जीत के कयास भी लगने शुरू हो जाते हैं। इस बीच अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू का कहना है कि उनके मुताबिक इस समय राष्ट्रपति पद की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि, संधू ने यह भी कहा कि अमेरिकी की राजनीति बेहद रोचक है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका के चुनाव में निर्वाचन प्रणाली 50 में से छह राज्यों पर निर्भर करती है। इसलिए छह राज्यों परिणाम बड़ा अंतर ला सकते हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि इसका फायदा रिपब्लिकन पार्टी को मिल सकता है।' तरणजीत सिंह संधू ने यह भी कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने कई चुनौतियां खड़ीं हैं लेकिन, ये चुनौतियां अवसर में भी बदल सकती हैं। संधू ने कहा 'दरअसल, जब आपके पास एक नया चेहरा होता है.

पहले दिन लोकसभा में हुआ हंगामा, आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करने के साथ सोमवार को संसद का बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले से लेकर रेलवे सुरक्षा जैसे कई प्रमुख मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरा। कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। वित्त मंत्री 23 जुलाई को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। एनडीए के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह मोदी सरकार का पहला बजट है। अप्रैल-जून में आम चुनाव होने के बाद यह संसद का पहला मानसून सत्र है।

सरकार ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पेश की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला की अनुमति से आर्थिक समीक्षा की प्रति सदन के पटल पर रखी। आर्थिक समीक्षा (सर्वे) सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा होती है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। देश में पहली बार आर्थिक समीक्षा 1950-1951 में पेश की गई थी जब यह बजट दस्तावेजों का ही हिस्सा होती थी।

लोकसभा

– लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' में कथित अनियमितता के विषय को लेकर सोमवार को सदन में सरकार पर प्रहार किया और दावा किया कि देश के करोड़ों छात्रों एवं देशवासियों को ''इस बात का यकीन हो गया है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक 'फ्रॉड' (धोखे वाली) है तथा जिसके पास पैसा है वह इस पूरी प्रणाली को खरीद सकता है''। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया और सवाल किया कि क्या 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा में सुधार से जुड़ा विधेयक निजी मेडिकल कॉलेजों के दबाव में वापस ले लिया था? उन्होंने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पूरी परीक्षा प्रणाली को 'बकवास' कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' में कथित अनियमितता को लेकर सोमवार को लोकसभा में

दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। इस पर प्रधान ने पलटवार किया और कहा कि वह इस सदन में उन पेपर लीक मामलों की पूरी सूची रख सकते हैं जो अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए थे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' से जुड़े मामले पर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए विपक्ष के आरोपों के संदर्भ में यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पिछले सात वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं।

संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में जहां एक प्रश्न के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया, वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शून्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, दोनों देने की मांग उठायी।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने पेरिस ओलम्पिक को लेकर भारत की तैयारी के विषय पर लोकसभा में सोमवार को हुई चर्चा को गैरजरूरी बताते हुए सरकार से मांग की कि उसे अब 2028 के ओलम्पिक की तैयारियों पर अभी से बात करनी चाहिए और सुझाव लेने चाहिए। भाजपा के डॉ. संजय जायसवाल ने सदन में नियम 193 के तहत 'आगामी ओलम्पिक के लिए भारत की तैयारी' विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने 'खेलो इंडिया' के लिए 1045 करोड़ रुपये दिये हैं, जो पिछली सरकार के खेल का संपूर्ण बजट भी नहीं हुआ करता था। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा ही है कि खेल जगत में भारतीय खिलाड़ी पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पहली बार ओलम्पिक में देश 10 से अधिक स्वर्ण पदक का आंकड़ा पार करेगा और भारतीय ओलम्पिक खिलाड़ी नया इतिहस बना सकेंगे।

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को अपराह्न करीब पौने तीन बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी तथा मंगलवार को उच्च सदन की बैठक लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के एक घंटे बाद शुरू होगी। उच्च सदन के 265वें सत्र की पहली बैठक राष्ट्रगान की धुन बजाये जाने के साथ शुरू हुई।

झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज, 45 क्लीनिक सील

बिलासपुर। जिले में मलेरिया, डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। इसके साथ ही झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई भी तेजी से हो रही है। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में 45 झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक सील किए गए हैं। जिसमें बिल्हा क्षेत्र में 17, कोटा में 12 तखतपुर और बिलासपुर में 8-8 फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई को गई है। इनमें दो लोग मेडिकल दुकान की आड़ में घर पर ही अस्पताल खोल मरीजों का इलाज कर रहे थे। यहां दो बेड और एलोपैथिक दवा का जखीरा मिला है। वहीं दो मरीज भी इलाज कराते मिले।

दरअसल, इन दिनों जिले में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप फैला है और ग्रामीण इलाकों में मरीज बड़ी संख्या में झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। बीते दिनों कोटा क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मलेरिया पीड़ित मरीज की मौत हो गई थी। जिसके बाद कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिले के सभी एसडीएम झोलाछाप डॉक्टर के क्लीनिक पर दबी देकर कार्रवाई कर रहे हैं।

इसी कड़ी में कोटा तहसील में बीती रात अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई की गई। जांच के बाद ग्राम पीपरतराई में संचालित बंगाली दवाखाना के संचालक रिपोन मंडल द्वारा एलोपैथी दवाईयां, इंजेक्शन पाए गए। उक्त व्यक्ति पर लगभग 6 माह पूर्व भी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही मस्तूरी क्षेत्र के दो डाक्टरों पर भी प्रशासन का डंडा चला। मेडिकल स्टोर में

ही अस्पताल संचालित किया जा रहा था। मस्तूरी और वेद परसदा में कार्रवाई करते हुए 2 डाक्टरों के क्लीनिक सील कर दिए गए हैं। तखतपुर क्षेत्र में एसडीएम द्वारा ग्राम सैदा, खैरी, सकर्रा, बेलमुंडी, सकरी, गनियारी, बेलपान, बीजा में संचालित अवैध क्लीनिक को सील किया गया।

बिलासपुर के चांटीडीह स्थित शिव कुमार धुरी के क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। क्लीनिक संचालक शिव कुमार धुरी ने एलोपैथी दवाईयां, इंजेक्शन रखने और इलाज करने संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इसके कारण क्लीनिक को सील किया गया। सेंदरी में पलाश कुमार राय के क्लिनिक में जांच की गई। चिकित्सा किए जाने संबंधी कोई भी प्रमाणित वैध अनुमति के दस्तावेज नहीं पाए जाने पर क्लिनिक सील किए जाने की कार्रवाई की गई। ग्राम सेमरताल में प्रसंजीत मलिक एवं ग्राम सेमरा में दरसराम साहू और पुष्पा साहू के क्लीनिक की जांच की गई। चिकित्सा किए जाने संबंधी कोई भी प्रमाणित दस्तावेज नहीं पाए जाने पर क्लीनिक सील करने की कार्रवाई की गई। ग्राम देवरीखुर्द में बंगाली क्लीनिक का अवैध रूप से संचालित करने पर क्लीनिक को सील कर दिया गया। इसी तरह सरकंडा इमलीमाठा में अवैध क्लीनिक सील की गई।

बिल्हा क्षेत्र में 17, कोटा क्षेत्र में 12, तखतपुर क्षेत्र में 8 और बिलासपुर शहरी क्षेत्र में 8 झोलाछाप डाक्टरों की क्लीनिक सील की गई। लगातार कार्रवाई के बावजूद अब भी ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में झोलाछाप डाक्टरों की क्लीनिक चल ही रही हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम इन अवैध क्लीनिक को सील तो कर रही है, लेकिन फर्जी डाक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

रायगढ़ विकास के नए पायदान पर होगा स्थापित : वित्त मंत्री चौधरी

- रायगढ़ विकास के नए पायदान पर होगा स्थापित
- बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट का किया लोकार्पण

रायगढ़। रायगढ़ शहर में नगर वासियों की सुविधा के लिए नया गार्डन बनेगा। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने आज इसके लिए 10 करोड़ रूपये की घोषणा की और अधिकारियों को स्थल का चिन्हांकन तथा जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वे आज शहर के नटवर स्कूल परिसर में बने बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण और कमला नेहरू गार्डन के उन्नयन कार्य के भूमि पूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण सहित सभी मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। आने वाले समय में सभी के सहयोग से रायगढ़ विकास के नए पायदान पर स्थापित होगा। उन्होंने शहर में हो रहे निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने

नटवर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20 लाख 33 हजार रुपए की लागत से बॉक्स क्रिकेट एवं 8 लाख 71 हजार रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट का विधिवत पूजा-अर्चना कर लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री श्री चौधरी ने बॉक्स क्रिकेट में क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट पर बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कमला नेहरू गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में 26 लाख 81 हजार रूपये की लागत से गार्डन उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। उन्नयन कार्य के अंतर्गत गार्डन में शौचालय, रिनोवेशन, साइड बाउंड्री वॉल, फब्बारा उन्नयन, प्रवेश द्वार, फुटपाथ आदि का निर्माण किया जाएगा।

बाल विकास अधिकारी के निरीक्षण के बाद बालगृह से दो अपचारी बालक फरार

- सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल

कोरबा। कोरबा में बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्था में ही सुधार की जरूरत है बालगृह का संचालन कुक और हाउस कीपर के भरोसे है जिसमें भराशाही बढ़ चढ़कर सामने आ रही है सुरक्षा व्यवस्था की बात कहें तो महज काम चलाऊ ही नजर आ रहा है जिसका फायदा उठाते हुए बाल अपचारी फरार हो गए। कटघोरा और पाली थाना क्षेत्र में अनाचार की घटना घटित हुई थी मामले में पुलिस ने दो अपचारी बालक के खिलाफ प्रावधानिक कार्यवाही की थी सिविल लाइन थाना अंतर्गत रिसदी चौक बाल संप्रेषण की भेजा गया था प्रतिदिन की तरह रात्रि में भोजन कर संप्रेषण गिरी को बंद कर दिया गया।

दोनों बालक भी अन्य अपचारी बालकों की तरह अपने बेड में सोने चले गए उनकी नींद सुबह खुल गई वह शौच के बहाने संप्रेषण गृह के पीछे हिस्से में पहुंचे जहां शौचालय की दीवार के सहारे कूद कर फरार हो गए घटना के कुछ ही देर पहले सुरक्षा में

तैनात नगर सैनिक संतोष केवट राउंड के बाद मुख्य द्वार में बैठा था अपचारी बालक के फरार होने की जानकारी तब लगी जब वह काफी देर तक कमरे में नहीं पहुंचे यह खबर आम होते ही महकमा में हड़कप मच गया इसकी सूचना बालक के परिजनों को दी गई। बालक के घर पहुंचने पर तत्काल अवगत कराने को कहा गया।

बालगृह के संचालन के लिए 16 अधिकारी कर्मचारी का सेटअप तैयार है लेकिन चार कर्मचारी ही कार्यरत हैं बाल गृह का संचालन कुक और हाउसकीपर के भरोसे चल रहा है उन पर ही विभाग पूरी तरह निर्भर है जिसका सीधा असर व्यवस्था पर पड़ रही है खास तो यह है कि रात में ही महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश निरीक्षण के लिए बाल गृह पहुंची थी उन्होंने बालको से चर्चा उपरांत सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए थे उनके निरीक्षक को महज कुछ ही घंटे बीते थे कि बालक भाग कर व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी।

संबंधित विभाग में इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को जहां बाल गृह में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू की है और उनकी तलाश में जुट गई है।

पुलिस की गश्त का असर चोर एटीएम मशीन को छोड़कर भागे

तिल्दा नेवरा। चोरों के दुस्साहस की दाद देनी होगी एटीएम मशीन से रुपए चोरी करने के बजाए नोटों से भरी एटीएम मशीन को ही उखाडने ले जाने की जुगत में थे लेकिन उसी समय गश्ती पुलिस के सायरन को सुन एटीएम मशीन को वहीं छोड़कर रफूचक्कर हो गये। एटीएम चोरी का यह पूरा मामला रायपुर जिले के तिल्दा का रविवार की मध्यरात्रि का है।

मिली जानकारी के अनुसार तिल्दा सिमगा मुख्य मार्ग पर सासाहोली में विश्राम गृह के पहले इंडिया नंबर वन का एटीएम लगा हुआ है,जहां बीती रात्रि लगभग 1.30 बजे अज्ञात चोरों ने उक्त एटीएम को चोरी करने का प्रयास किया। अज्ञात चोरों ने सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को निष्क्रिय किया और उक्त एटीएम को उखाड़ कर बाहर ले आये और एटीएम के शटर को बंद कर दिया। बताया जाता है कि एटीएम मशीन में लाखों रुपए भरे हुए थे। जिस समय अज्ञात चोर इस घटना को अंजाम देने में लगे हुए थे ठीक उसी समय नेवरा पुलिस की टीम गश्त पर निकली हुई थी। पुलिस वाहन में लगे सायरन को सुनकर अज्ञात चोर एटीएम मशीन को वहीं बाहर छोड़कर फरार हो गए। इससे पूर्व भी तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरोरा में इंडिया नंबर वन के एटीएम मशीन को अज्ञात चोर उखाड़ कर ले गए थे जिसका आज तक सुराग नहीं मिला है और इस बार फिर से चोरों ने इसी एटीएम को अपना निशाना बनाया। पुलिस की सतर्कता से यह वारदात टल गई। इंडिया नंबर वन कंपनी ने अपने एएटीएम तो लगा दिये लेकिन इसके सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। इसके अलावा इस इलाके में कई बैंकों में भी एटीएम लगा हुए जहां भी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है। गार्ड नहीं होने से एटीएम मशीन लूटने वाले गिरोह एटीएम को निशाना बना रहे है।

कोंडागांव में सेग्रीगेशन शेड का निर्माण अधूरा, कबाड़ बन रहे सभी शेड

कोंडागांव। स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य दो अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करना था। इस अभियान के अंतर्गत, सभी ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन के लिए सेग्रीगेशन शेड बनाने की योजना बनाई गई। इन शेडों का मुख्य उद्देश्य गीला और सूखा कचरा का प्रबंधन करना था, जिसमें महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से गांवों में घर-घर से कचरा एकत्रित कर उसे कचरा प्रबंधन यूनिट तक भेजा जाता है। वहां सुखा कचरा और गीला कचरा से कंपोस्ट खाद और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं।

कोंडागांव जिले में वर्ष 2019-20 से अब तक 567 सेग्रीगेशन शेड बनाए जाने की स्वीकृति मिली है, जिनमें से 356 शेड बन चुके हैं और 211 शेड अभी निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 2021-22 से पहले स्वीकृत हुए 42 सेग्रीगेशन शेड आज तक निर्माणाधीन हैं। सेग्रीगेशन शेड के लिए जरूरी सामान जैसे रिक्शा , हाथ गाड़ी, शेड सभी अब कबाड़ में तब्दील होने लगे हैं। पूर्ण हो चुके 356 सेग्रीगेशन शेड में से किसी भी जगह शेड का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई ने संबंधित तकनीकी सहायकों और जनपद पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी 567 स्वीकृत सेग्रीगेशन शेड को जल्द ही पूरा कराया जाएगा और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जाएगा कि महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उनकी पूरी उपयोगिता सुनिश्चित करें।

भोई ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करना है। सेग्रीगेशन शेड का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण

होगा, बल्कि महिलाओं के स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद मिलेगी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोंडागांव जिले में चल रही गतिविधियों ने स्थानीय समुदाय को भी जागरूक किया है। गांवों में स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और वे इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सेग्रीगेशन शेड के निर्माण से स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

भोई ने आगे बताया कि जिन शेडों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, उनके लिए तकनीकी सहायकों को नोटिस जारी कर शीघ्रता से निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, महिला स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर उन्हें कचरा प्रबंधन के कार्य में शामिल किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की दिशा में अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सकें। कोंडागांव जिले के सभी सेग्रीगेशन शेडों को जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को साकार किया जा सके और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता का स्तर बढ़ाया जा सके।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जांजगीर चांपा में जयकारों से गूंजे शिवालय

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के छोटा उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध बाबा कलेश्वर नाथ मंदिर में सावन के पवित्र माह की शिवालय में गुंजा हर हर महादेव के का नारा और श्रद्धालू जल अभिषेक करने पहुंचे। आज सावन माह का पहला सोमवार है। जिला मुख्यालय से छह किलो मीटर दूर हसदेव नदी के तट पर स्थित ग्राम पीथमपुर शंकर भगवान के प्रसिद्ध मंदिर बाबा कलेश्वर नाथ में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। जो दर्शन ओर जल अभिषेक करने हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। बाबा कलेश्वर नाथ का मंदिर लगभग 450 वर्ष पुराना है। मंदिर परिसर में समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी मंदिर के सभी द्वार पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। श्रद्धालु शिव मंदिर में पूजा कर अपने-अपने घर परिवार की मंगल कामनाओं की मांग कर रहे हैं। बाबा कलेश्वर नाथ मंदिर के शिवलिंग की जलहरी के जल का विशेष महत्व है। साथ ही साथ जिले के सभी शिवालयों में सोमवार सुबह से ही जय भोलेनाथ और बम-बम भोले का नारा गूंज रहा है।

अपना भविष्य गढने के साथ-साथ तंदरुस्त भी रहेंगे बच्चे

भिलाई। सामाजिक सेवा संस्थान गोल्डन एंपथी (जीई) फाउंडेशन की पहल पर सांदीपनिबालक हॉस्टल फरीद नगर में शिक्षण सामग्री और खेल का सामान वितरित किया गया। इस दौरान यहां रह रहे बालकों ने इन उपहारों के लिए खुशी जाहिर की और फाउंडेशन के पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा विभाग से आए अधिकारियों से वायदा किया कि वे पढ़ाई के साथ-साथ खेलों पर भी पूरा ध्यान देंगे। जीई फाउंडेशन ने अपने शिक्षा अभियान का चौथा चरण समग्र शिक्षा अभियान के तहत सांदीपनि बालक हॉस्टल फरीद नगर में आयोजित किया। जीई फाउंडेशन के संयोजक प्रदीप पिल्लई ने यहां बच्चों के बीच पहुंच कर उनसे संवाद किया और करियर मार्गदर्शन दिया। सहायक परियोजना अधिकारी गीता शर्मा ने बच्चों को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि यदि गुरु ने हमें ज्ञान दिया है तो उसकी तुलना में पृथ्वी में कुछ भी नहीं है। इस दौरान जीई फाउंडेशन की ओर से के वी विनोद और अजीत सिंह ने बच्चों को खेलों में ध्यान देने प्रोत्साहित किया।

छत्तीसगढ़ में रेत बनी सोना, मंत्री ने बताई वजह

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद से पीएम आवास को लेकर काम में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है।जिसे लेकर बीजेपी के नेता पूरे प्रदेश में बयान देते नजर आ रहे हैं। पहले राजनांदगांव में डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर बयान दिया था।वहीं अब कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पीएम आवास को लेकर बयान दिया है। मंत्री रामविचार नेताम से जिले में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर पूछे जाने सवाल पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि बघेल सरकार के कार्यकाल में बंद हो चुकी प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी मात्रा में स्वीकृति अब मिली है। रामविचार नेताम ने कहा विष्णुदेव साय सरकार के शासन में पीएम आवास को लेकर बड़ी संख्या में स्वीकृति मिली है। इस दौरान रेत और गिट्टी की मांग बढ़ी है। इसलिए रेत और गिट्टी सप्लाई करने वाले इस मांग को लेकर गलत काम में लगे हैं। लेकिन गलत काम करने वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तीन युवकों ने बैंक मैनेजर और कर्मचारियों को पीटा

तखतपुर। बैंक में घूसकर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर से मारपीट करने और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीडित मैनेजर ने तखतपुर थाने में मामले की शिकायत की है। यह मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक का है। तीन युवकों ने एसबीआई बैंक कर्मियों से मारपीट की है। इस घटना के बाद बैंक में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा कि लोन सेटलमेंट करने को लेकर तीन युवकों ने विवाद किया। बैंक कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए तीनों युवकों ने मारपीट भी की। इस घटना के बाद बैंक में लेनदेन प्रभावित है। इस मामले की शिकायत एसबीआई मैनेजर अंकित भूषण लाल और फील्ड मैनेजर प्रेम कुमार जायसवाल ने तखतपुर थाने में की है। इस घटना के बाद बैंक में तनाव की स्थिति है। वहीं एसबीआई बैंक के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है।

पेंड्रा में टला बड़ा हादसा अनियंत्रित ट्रक पलटा

पेंड्रा। पेंड्रा के अमरपुर मार्ग पर सोमवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जिसमें एक रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटा है। हादसे में राहत की बात यह रही कि चालक-परिचालक दोनों सुरक्षित हैं। ट्रक रेत लेकर यूपी के शंकरगढ़ से रायपुर आयरन फैक्टरी जाने को निकला था। मामला पेंड्र थानाक्षेत्र के पेंड्रा अमरपुर मुख्यमार्ग का है। जहां पर आज सुबह लगभग चार बजे के आसपास एक ट्रक जो उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ से रेत लेकर रायपुर के आयरन फैक्टरी के लिए निकला था और ट्रक पेंड्रा से अमरपुर जाने वाले मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गया। राहत की बात यह रही कि ट्रक जिस जगह पर पलटा। उस जगह पर बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। ट्रक सीधे उसमें नहीं टकराया। अगर ट्रक बिजली ट्रांसफार्मर में टकरा जाता तो बड़ा हादसा और बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि, ट्रक हादसे में ट्रांसफार्मर में लगे बिजली के केबल टूट गए है। जिससे आसपास के काफी घरों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है।

चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल के निर्माण में प्रयुक्त है सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र का इस्पात

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र सहित सेल के अन्य इस्पात संयंत्रों ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण हेतु 16,000 टन स्टील की आपूर्ति की है, जिसके अंतर्गत प्लेट्स, टीएमटी बार और स्ट्रक्चरल्स शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बना यह पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है।

किसी भी निर्माण प्रक्रिया और औद्योगिक गतिविधि के लिए स्टील सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। प्रकाशित समाचारों के अनुसार इस पुल के निर्माण में लगभग 29,000 मीट्रिक टन स्टील, 10 लाख क्यूबिक मीटर अर्थवर्क, 66,000 क्यूबिक मीटर से अधिक कांक्रीट तथा 84 किलोमीटर रॉक बोल्ट और केबल एंकर का प्रयोग किया गया है। 1.3 किलोमीटर लंबा यह पुल पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा है। अभियांत्रिकी की अभिनव कृति यह पुल 266 किमी प्रति घंटे हवा की तेज रफ्तार और उच्चतम तीव्रता के भूकंपीय तरंगों का सामना करने में सक्षम है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना (यूएसबीआरएल) के अंतर्गत यह पुल जो कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे घुमावदार खंड का हिस्सा है, इस क्षेत्र में आवागमन को सुलभ करेगा।

यह पुल क्षेत्र में तेज और कुशलतम परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा तथा सभी मौसम में उपयोग किया जा सकेगा। चेनाब रेल पुल वस्तुतः देश के लिए सामरिक महत्व की परियोजना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), जो अपने इस्पात संयंत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इस्पात का उत्पादन करती है, ने राष्ट्रीय महत्व की कई ऐसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे बांधों, पुलों, सुरंगों, फ्लाईओवरों और एक्सप्रेसवे सहित ऊर्जा क्षेत्र व रक्षा क्षेत्र में प्रयोग हेतु वांछित ग्रेड के इस्पात की आपूर्ति

की है।

सेल के इस्पात संयंत्रों ने जम्मू-कश्मीर में निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल में प्रयोग हेतु 6690 टन टीएमटी उत्पाद, 1793 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 7511 टन स्टील प्लेट्स, हॉट स्ट्रिप मिल प्रोडक्ट और चेकर्ड प्लेटों सहित कुल 16,000 टन इस्पात की आपूर्ति की है। पुल के निर्माण हेतु सेल द्वारा आपूर्ति की गई इस्पात में से, भिलाई इस्पात संयंत्र ने 5922 टन टीएमटी स्टील, 6454 टन प्लेट्स और 56 टन स्ट्रक्चरल स्टील सहित कुल 12,432 टन इस्पात की आपूर्ति की है। सेल के बर्नपुर स्थित इस्को स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील लिमिटेड ने भी स्टील की आपूर्ति की है।

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के इस्पात का उपयोग विभिन्न सामरिक क्षेत्रों और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में किया गया है। भारतीय रेलवे के लिए वांछित ग्रेड के रेल्स उत्पादन के अलावा सेल-बीएसपी चौड़ी, मोटी और हेवी प्लेटों की विविध श्रृंखला का उत्पादन तथा विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु वैल्यू एडेड स्पेशल स्टील ग्रेड की रोलिंग करता है। संयंत्र द्वारा उत्पादित टीएमटी उत्पादों की पूरी श्रृंखला भूकंपरोधी और जंगरोधी गुणों के साथ उच्च गुणवत्ता की है। इसके अतिरिक्त संयंत्र चैनल्स, एंगल्स और बीम्स सहित स्ट्रक्चरल ग्रेड स्टील का भी उत्पादन करता है। सेल-बीएसपी में उत्पादित इस्पात का उपयोग रक्षा, ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के साथ ही कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पुलों, राजमार्गों, सुरंगों, फ्लाईओवर सहित भूकंपीय और संक्षारण संभावित क्षेत्रों में ऊंची इमारतों और औद्योगिक संरचनाओं में, भारी मशीनरी, तेल और गैस क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों आदि में किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि भिलाई द्वारा उत्पादित स्टील का उपयोग बांद्रा-वर्ली सी-लिंक के साथ ही मुंबई में अटल सेतु, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग और राष्ट्रीय महत्व की कई अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण में किया गया है। भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत, आईएनएस विक्रांत और अन्य युद्धपोतों के निर्माण में भी सेल-भिलाई द्वारा उत्पादित स्टील का उपयोग किया गया है। बुलेट ट्रेन परियोजना हेतु सेल-बीएसपी द्वारा बड़ी मात्रा में टीएमटी बार्स की आपूर्ति की गई है। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने देश की राजधानी में निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना में उपयोग हेतु भी टीएमटी उत्पादों की आपूर्ति की है।

प्रश्नकाल में वन अधिकार पट्टा में फर्जीवाड़ा पर हंगामा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। 26 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व संसदीय सचिव मकसूदन लाल चंद्राकर, सदस्य अमीन साय, लक्ष्मी प्रसाद पटेल और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य अग्नि चंद्राकर को श्रद्धांजलि दी गई।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में सबसे पहले राष्ट्रगान और छत्तीसगढ़ राजकीय गीत हुआ। इसके बाद स्पीकर ने निधन का उल्लेख करते हुए सदस्यों का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने भी दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप, कवासी लखमा, उमेश पटेल, लालजीत सिंह राठिया ने भी दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। दिवंगतों के सम्मान में सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्नकल विधानसभा में प्रश्नकाल विधानसभा में नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में पहला सवाल विधायक जनक ध्रुव ने पूछा। उन्होंने सवाल किया कि गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा पर सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इसकी शिकायत कलेक्टर को मिली थी। कलेक्टर ने इसकी जांच के निर्देश गरियाबंद के सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग और अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि संजय नेताम के नाम से शिकायत की गई। इनके द्वारा वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का कोई आवेदन नहीं दिया गया। इसका प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती जल्द मानसून सत्र में सीएम ने की घोषणा

कलेक्टर को भेजा गया और इस आरोप को निराधार मानते हुए 21 जुलाई 2022 में विलोपित किया गया। इस तरह इस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती।

जनक ध्रुव ने कहा जो पात्र नहीं है उनके नाम पर सैंकड़ों एकड़ वनभूमि पट्टा बनाया गया है जबकि हितग्राहियों को वन पट्टा नहीं मिल पा रहा है। इस पर दोषियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जिस समय ये गड़बड़ी हुई वो कांग्रेस शासनकाल में हुआ। इस पर विधायक यदि कोई तथ्य पेश करेंगे तो इस पर जांच की जाएगी।

पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछा, ये प्रकरण साल 2018 का था। 2018 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इससे पहले भाजपा की सरकार थी। जब इसकी शिकायत मिली उसके बाद ग्राम वन समिति, एसडीएम लेवल और कलेक्टर स्तर पर जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खड़े होते हैं। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा के जवाब देने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बीच में टोकते हुए कहा कि साफ जवाब दे दिया गया है। इसके बाद सदन में बहस शुरू हो गई। इसके बाद पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मांगपत्र में फर्जी साइन करने का मुद्दा उठाया और मामले की जांच की मांग की।

विधायक मोतीलाल साहू ने शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल सदन में उठाया। उन्होंने पूछा कि माना कैंप में हिंदी मीडियम स्कूल में सिर्फ 2 टीचर है। वहीं माना हायर सेकेंड्री स्कूल में सिर्फ 3 शिक्षक है। चार कक्षाओं में तीन टीचर होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में टीचर्स की कब तक भर्ती होगी। इस सवाल के जवाब में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि- पूरे देश में 26 स्टूडेंट में एक शिक्षक का औसत है लेकिन छत्तीसगढ़ में 21 स्टूडेंट में एक शिक्षक है। फिर भी यहां टीचर्स की कमी है। प्रदेश में 300 बिना टीचर्स के स्कूल है साढ़े 5000 स्कूलों में टीचर है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे की जाएगी। इस पर टोकते हुए धमतरी विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल पूछा कि ये भी बात दें कि शहरी क्षेत्र के या प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल है जिसमें सरप्लस टीचर है। इस पर सीएम ने कहा कि इसकी अभी जानकारी नहीं है, आपको अलग से दी जाएगी।

प्रश्नकाल में रायपुर के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को लेकर सवाल हुआ। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर जिला में 7 हजार 939 शिक्षकों के पद हैं। इनमें 1 हजार 954 पद खाली हैं। साय ने बताया कि पदोन्नति अंतर्गत भरे जाने वाले पदों में पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों में नियमित भर्ती के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि मेरे क्षेत्र में 90 स्कूल है जिनमें से अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कई स्कूल हैं जो शिक्षक वीहिन है। रिक्त पदों पर नियमित भर्ती के लिए शासन क्या प्रयास कर रहा है और रिक्त पदों पर भर्ती कब तक शुरू की जावेगी ?

इसके जवाब में विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अजय चंद्राकर ने कहा कि ऐसे कितने स्कूल हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षक हैं। साय ने कहा कि अभी यह दे पाना संभव नहीं है।

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

विधानसभा शुरू होने से पहले रविवार रात छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में हुई। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने ली। जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस विधायक ओर सांसद सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। दीपक बैज ने कहा विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों के साथ पार्टी गतिविधियों और आने वाले 24 जुलाई को विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही संबंधित विधायक और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसकी जवाबदारी सौंपी गई है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस 24 जुलाई को ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। भूपेश बघेल ने कहा 6 महीने के अंदर ही सुशासन की पोल खुल गई है। सारे संगठन रसोइया से लेकर पटवारी, शिक्षक, अतिथि शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राशन कार्ड भी बंट गए हैं पांच किलो मिलना शुरू होगा।

संक्षिप्त समाचार

सावन के पहले सोमवार पर मुख्यमंत्री साय ने भोलेनाथ को किया नमन

रायपुर। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था। देशभर में भगवान शिव की भक्ति के लिए मंदिरों में सैलाब उमड़ गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले के भोरमदेव बाबा के मंदिर का वीडियो शेयर करते हुए भगवान शिव को नमन किया और सभी के लिए प्रार्थना की है। सीएम साय ने लिखा कि पवित्र सावन मास के प्रथम दिवस पर आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के खजुराहो भोरमदेव मंदिर के बारे में। भोरमदेव बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा के भोरमदेव मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किये और पूजा अर्चना की। बता दें, श्रावण मास यानि सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति का विशेष महत्व है। इस बार सावन महीन के शुरुआत ही सोमवार के साथ हुई है और इस मौके पर सभी ज्योतिर्लिंग और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी सुबह से ही शिव मंदिरों में महादेव के जलाभिषेक और दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग भगवान शिव के नाम और मंत्रो का जाप कर रहे हैं।

सांसद ज्योत्सना महंत व टीएस सिंहदेव पहुंचे विधानसभा

रायपुर। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कोरबा लोकसभा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत पहुंचीं। दोनों ही अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे थे। इस दौरान विधानसभा के सदस्यों ने उनका अभिवादन किया।

सीएम के मीडिया सलाहकार ने साइबर थाने लिखाई रिपोर्ट

रायपुर। सोशल मीडिया एकाउंट फेसबुक का क्लोन बनाकर ठगी करने के लिए मैसेज भेजना कोई नई बात नहीं है। लेकिन ठगों के हौसले देखें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा को भी लपेटे में ले लिया। पहले तो झा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने शुभचिंतकों को सचेत करते रहे लेकिन परेशान होकर आखिर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है। इस मामले की शिकायत कर पंकज झा ने ऐसे लोगों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। आरोपी ने रायपुर के एक व्यक्ति को मैसेज कर नंबर मांगा और फिर मैसेज किया है कि सीआरपीएफ कैंप से मेरा एक दोस्त आशीष कुमार आपको कॉल करेगा, मैं आपका नंबर उसे भेज दे देता हूं, वह सीआरपीएफ अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है। वह अपने घरेलू फर्नीचर का सामान सेकेंड हैंड बेच रहे हैं, सभी वस्तुएं अच्छी है और कीमत बहुत सस्ती है। आप चाहें तो ले सकते हैं, इसकी शिकायत साइबर थाने में कर दी गई है। रायपुर में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।

महादेवसाल स्टेशन में 6 गाड़ियों का अस्थायी ठहराव

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा महादेवसाल मंदिर में आयोजित श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की विशेष सुविधा हेतु दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के महादेवसाल स्टेशन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने/चलने वाली गाड़ी 6 गाडियों का 2 मिनट के लिए अस्थायी ठहराव की सुविधा दी गई है। अस्थायी ठहराव की यह सुविधा आज से प्रभावी होकर 22 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 13287/13288 दुर्ग-आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस, 22 अगस्त तक प्रत्येक रविवार व सोमवार को महादेवसाल स्टेशन में 2 मिनट के लिए रुकेगी। गाड़ी संख्या 18109/18110 टाटानगर-इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस, 22 अगस्त तक प्रतिदिन महादेवसाल स्टेशन में 02 मिनट के लिए रुकेगी। गाड़ी संख्या 18113/18114 टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस, 22 अगस्त 20 तक प्रतिदिन महादेवसाल स्टेशन में 2 मिनट के लिए रुकेगी।

आवासीय तीरंदाजी खेल अकादमी के लिए चयनित 40 खिलाड़ियों की सूची जारी

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा रायपुर में संचालित आवासीय तीरंदाजी अकादमी के लिए 20 बालक तथा 20 बालिकाओं का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन 25 एवं 26 जून को रायपुर के स्वामी विवेकानन्द स्टेडियम एवं खेल संचालनालय परिसर तीरंदाजी एरिना में सम्पन्न हुआ। खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम के निर्देश पर चयन ट्रायल के नोडल अधिकारी चेतन कुमार श्रीवास प्रशासक खेल अकादमी रायपुर के द्वारा चयन ट्रायल सुव्यवस्थित तरीके से कराया गया। चयनकर्ताओं के द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस से संबंधित मोटर एबिलिटी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, स्पोर्ट्स स्कील टेस्ट एवं मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिये गए। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों को ही प्रदर्शन के आधार पर मेरिट क्रमानुसार 13 से 17 वर्ष आयुवर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में भाग लिया, इसमें राज्य के जिले रायपुर से 05 बालिका और 09 बालक, सरगुजा से 07 बालिका, धमतरी से 02 बालक और 04 बालिका, महासमुंद से 05 बालिका और 02 बालक, नारायणपुर से 03 बालक, बिलासपुर से 01 बालक, कोण्डागांव से 01 बालक एवं गरियाबंद जिले से 01 बालिका का चयन किया गया है। इन चयनित खिलाड़ियों को 10 दिवस के भीतर अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा।

प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी को रखने वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है: साय

रायपुर। सत्तापक्षा के विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला विधानसभा में उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन को बताया कि प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी को रखने वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

मानसून सत्र के पहले दिन धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि क्या यह सही है कि प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने के नियम/निर्देश हैं? यदि हाँ तो वे नियम/निर्देश क्या हैं? क्या प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारियों को रखने हेतु

वित्त विभाग की स्वीकृति जरूरी है तथा इस हेतु क्या नियम हैं? मुख्यमंत्री ने बताया कि आबकारी विभाग के अंतर्गत दो निगम क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड संचालित है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड- यह सही है कि प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने के नियम/निर्देश हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी को रखने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति प्राप्त की जाती है। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड- प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने हेतु संचालक मंडल द्वारा सेवा शर्तों का अनुमोदन किया जाता है। निगम में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जाते हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ हुआ।

प्रदेश में फसलों के नुकसान पर मुआवजा राशि वितरण का विस में उठा मामला

रायपुर। कांग्रेस शासन काल में मंत्री रहे व वर्तमान विधायक उमेश पटेल ने प्रदेश में बिगड़े मौसम एवं ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से वर्ष 2023-24 से जून, 2024 तक किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? कितनी राशि वितरित की गयी है? कितनी शेष है? क्या बेमौसम बारिश से जनहानि या पशुहानि भी हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? का मामला मानसून सत्र के पहले दिन उठाया। जवाब में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने बताया कि प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु 44 करोड़ 84 लाख 92 हजार 1 सौ 64 रूपये स्वीकृत की गई है। 21 करोड़ 35 लाख 62 हजार 6 सौ 36 रूपये वितरित की गई है। 23 करोड़ 49 लाख 29 हजार 5 सौ 28 रूपये शेष है। आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत कर भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पटेल ने मंत्री से पूछा कि आर.बी.सी. 6/4 के तहत कितना - कितना मुआवजा देने का नियम है ? मंत्री वर्मा ने बताया कि 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर सिंचित क्षेत्र के लिए रुपये 17000.00 प्रति हेक्टेयर, न्यूनतम रुपये 2000.00 एवं असिंचित क्षेत्र के लिए रुपये 8500.00 प्रति हेक्टेयर, न्यूनतम रुपये 1000.00 अनुदान सहायता देने का प्रावधान है।

गुढ़ियारी आग मामले में 8 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस

रायपुर। माह अप्रैल 2024 में गुढियारी में स्थित विद्युत कंपनी के डिपो और कार्यालय में आग लग गई थी जिसे बुझाने के लिए वहां के रहवासियों के अलावा नगर निगम और फायर बिग्रेड की टीम ने पूरी जान लगा दी और दो दिनों तक यहां आगमन पूरी तरह से बाधिक कर दिया गया था। इस मामले में 8 अधिकारी और कर्मचारियों को दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है लेकिन उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है। आगजनी बूझाने के लिए एक पानी की टंकी और पाइप क्षतिग्रस्त हो गई जिसके बदलने के लिए नगर निगम रायपुर को 2,37,000 का भुगतान किया जा चुका है। जले एवं खराब सामग्री की नीलामी तथा शेष राशि की क्षतिपूर्ति कंपनी के नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। ये बातें छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेताप्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए।

महंत ने तारांकित प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री से सवाल किया कि एक शासकीय विद्युत कंपनी के गुढियारी (रायपुर) में स्थित डिपो और कार्यालय में माह अप्रैल, 2024 में लगी आग से क्या-क्या नई तथा पुरानी

सामग्रियां नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई ? उनकी मात्रा और लागत बताइए? मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि विद्युत कंपनी के गुढियारी (रायपुर) में स्थित डिपो और कार्यालय में माह अप्रैल-2024 में लगी आग में नई एवं पुरानी सामग्रियाँ नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत 50.22 करोड़ रुपये अनुमानित है। महंत ने फिर पूछा कि घटना स्थल के आसपास के निवासियों की चल-अचल सम्पत्तियों की कितनी-कितनी क्षति हुई तथा उनको कितना-कितना मुआवजा भुगतान किया गया तथा कितना शेष है? मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना के तुरंत पश्चात् नगर निगम, रायपुर द्वारा घटना स्थल के निकट स्थित निवासियों की क्षतिग्रस्त पानी की टंकी एवं पाईप को बदलने का कार्य किया गया था। नगर निगम द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु रु. 2,37,000.00 का देयक विद्युत कंपनी को दिया गया था जिसका भुगतान विद्युत कंपनी द्वारा कर दिया गया और कोई भी राशि शेष नही है।

महंत ने सवाल किया कि डिपो की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कर्तव्य किन-किन अधिकारियों का था? कर्तव्य पालन में चूक करने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं और उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? क्षतिपूर्ति की क्या व्यवस्था है?मुख्यमंत्री साय ने सदन को बताया कि डिपो की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कर्तव्य कार्यपालन अभियंता (क्षेत्रीय भंडार), स्टोर कीपर एवं उक्त तिथि पर तैनात नियमित कर्मचारी तथा बाह्य स्त्रोत से नियुक्त सुरक्षा कर्मचारी दुर्गेश इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) के कर्मचारी थे। वर्तमान में जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 08 अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कारण बताओं सूचना जारी किया गया है एवं कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है। जले एवं खराब सामग्री की नीलामी तथा शेष राशि की क्षतिपूर्ति कंपनी के नियमों के अंतर्गत की जावेगी।

फिल्टर प्लांट की पाइप लाइन में कचरा फंसने से टंकियों में पानी का सप्लाई रुका

■ जल संकट का खतरा!, अधिकारी अपनी टीम से साथ सफाई में जुटे

रायपुर। खारुन नदी स्थित वाटर वर्ल्ड फिल्टर प्लांट की पाइप लाइन में बारिश का कचरा जमा होने की वजह से आज शहर की सभी टंकियों में पानी की आपूर्ति नहीं हुई। जिसकी वजह से लोगों को पानी की काफी दिक्कत हो रही है। वहीं पाइपलाइन में जमे कचरे की सफाई के लिए जल विभाग के अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अगर सफाई का कार्य पूरा नहीं हो पता है तो लगभग राजधानी के 4 लाख घरों में जल संकट आ सकती है। बताया जा रहा है कि आज डीडी नगर सेक्टर 1 टंकी और डंगनिया पानी टंकी से भी सुबह पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है।

वाटर वर्ल्ड फिल्टर प्लांट की पाइप लाइन में कचरे जमने की सूचना पर लल्लूराम डॉट कॉम की टीम भी मौके पर पहुंची। जहां देखा गया कि फिल्टर प्लांट के लिए लगे दो बड़े पाइप में जल स्तर काफी कम है। यह आप वीडियो में भी साफ सकते है।

सामान्य दिनों में इन पाइप्स में पानी फूल आता है लेकिन कचरा फंसने के कारण पानी आधा से भी काम में आ रहा है।

निगम के अधिकारी (कार्यपालन अभियंता) ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बारिश की वजह से कल रात आठ बजे के बाद खारुन नदी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। खारुन नदी का लेवल चार फीट से ऊपर हो गया है। पानी का लेवल ज्यादा होने से नदी किनारे के जितने भी जलकुंभी और कचरे हैं वो बह कर इंटेक बेल के नेट में लगातार फंस रहे हैं। जब हैवी कैपेसिटी का पंप पानी खींच रहा है तो उसमें जलकुंभी के चिपकने से वाटर पंपिंग चलाने में असुविधा हो रही है और पानी फिल्टर नहीं हो पा रहा है। ऐसी समस्या रात को उत्पन्न होने के बाद गोताखोर कचरा हटाने के काम में लग गए थे लेकिन रात होने के कारण सफाई काम उतना नहीं हो पाया। इसलिए आज सुबह चार बजे फिर से गोताखोरों को लगाया है। जसिके बाद से कुछ हद तक पानी खिंचा जा रहा है और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं।

पाइप लाइन की सफाई और राजधानी के आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई सामान्य कब हो सकेगी। इस सवाल पर कार्यपालन अभियंता ने कहा कि सप्लाई नार्मल तो नहीं कर सकते लेकिन 60 प्रतिशत हम पानी दे देंगे। सुबह हमारे गोताखोर लगे हैं सामान दिनों में जैसे टंकी में सात मीटर जो पानी आता था वह लगभग पांच मीटर भरा पाएंगे। कल तक इसमें कमी आने की संभावना है और एक-दो दिन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद

Phone No. :-07749-222370, Email Id : ee.res.balod@gov.in

(Zonal Tender) सूचना तृतीय बार

क्रमांक / 04 / व.ले.लि./ ग्रा.यां.से. / 2024-25 बालोद, दिनांक 19.07.2024

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से निम्न दर्शित क्षेत्रीय निविदा (Zonal Tender) हेतु जनपद पंचायत (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु) डौण्डी / गुण्डरदेही एवं डौण्डीलोहारा रुप (ब. स. द एवं ई) निविदा हेतु प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 01.11.2021 से एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रचलित तथा सिविल कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01.01.2015 एवं नलकुप खनन हेतु प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची की मुद्रित एवं अद्यतन संशोधित दरों पर निविदा प्रतिशत दर पर दिनांक 30.07.2024 को अपरान्ह 5.30 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त निविदाओं को दिनांक 31.07.2024 को 11:30 बजे पूर्वान्ह में खोली जावेगी:-

(1) निविदा राशि रू. 20.00 लाख प्रत्येक ग्रुप
(2) अमानत राशि रू. 20000.00 प्रत्येक ग्रुप
(3) निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 750.00 प्रत्येक ग्रुप

निविदा दस्तावेज कार्यालय द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा, ऑनलाईन पोर्टल https://res.cg.gov.in/ अन्य पोर्टल जिसे निविदा विज्ञप्ति में दर्शाया गया है दिनांक 19.07.2024 से डाउनलोड किया जा सकता है एवं कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

जी-242501232/6

बेरोजगारी-महंगाई जैसे मुद्दों ने घटाईं भाजपा की सीटें

पी. चिदंबरम

अर्थव्यवस्था के कई अन्य ईमानदार शुभचिंतकों की तरह मैं भी हमेशा केंद्रीय बजट को पेश होने की पूर्व संध्या पर पढ़कर और विचार कर लिखता हूं और फिर अक्सर बजट के दिन संसद भवन से निराश होकर निकलता हूं। इसके बाद मैं लोगों के पास जाता हूं। विधायकों, अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और सबसे बढ़कर पार्टी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बात करता हूं। इनसे मुझे जमीनी हकीकत का पता चलता है, खासकर स्थानीय बाजारों में होने वाली हलचलों के बारे में। पिछले 10 वर्षों के दौरान लगभग हर साल मैंने पाया कि बजट में की गई 'घोषणाएं' 48 घंटों में गायब हो जाती हैं और चर्चाएं बंद हो जाती हैं। इस निराशाजनक प्रदर्शन का मुख्य कारण बजट बनाने वालों का वास्तविकता से दूर रहना है, जिससे वे आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहते हैं। साल 2024-25 का बजट 23 जुलाई, 2024 को पेश किया जाएगा। आर्थिक स्थिति के सूक्ष्म मूल्यांकन से पता चलता है- युवाओं के साथ-साथ परिवारों और सामाजिक शांति के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। दर्जनभर खाली पदों के लिए हजारों की संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं। परीक्षाओं में शामिल होते हैं और इंटरव्यू देते हैं। प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। रिश्वत दी जाती है। कुछ परीक्षाएं या इंटरव्यू अंतिम समय में रद्द होना भारी निराशा का कारण बनते हैं। इसी का परिणाम है बेरोजगारी का भयंकर रूप से बढ़ना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी की दर 9.2 प्रतिशत है। कहने को तो कृषि, निर्माण और गिग इकोनॉमी के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है। युवा ऐसी नियमित नौकरियां चाहते हैं, जिनमें उन्हें सुरक्षा और उचित वेतन भी मिले। इस तरह की नौकरियां सरकारी निकायों में उपलब्ध हैं। 2024 की शुरुआत में ऐसे पदों पर 10 लाख रिक्तियां थीं, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें भरने के लिए कोई इच्छा जताई हो। इस तरह की नौकरियां विनिर्माण क्षेत्र और वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, शिपिंग, हवाई परिवहन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और शोध के क्षेत्र में पैदा की जा सकती थीं। विनिर्माण उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद के 15 प्रतिशत पर आकर रुक गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि भारतीय प्रमोटरों ने इस क्षेत्र में निवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। विनिर्माण और उच्च-मूल्य सेवाओं के तेजी से विस्तार के लिए आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन और विदेशी निवेश के साथ विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साहसपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। महंगाई या मुद्रास्फीति दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा मापी गई थोक मूल्य मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर है। सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत और खाद्य मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत है। चूंकि भारत के हर हिस्से में सामानों की सप्लाई एक जैसी नहीं है, इसलिए अलग-अलग राज्यों और जिलों के दूरदराज इलाकों में कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। अगर भारतीय आबादी के 20 से 30 प्रतिशत को छोड़ दिया जाए तो हर कोई महंगाई से प्रभावित हुआ है। इस वजह से कुछ लोगों में नाराजगी भी है। हालांकि बजट के भाषणों और आवंटन में बेरोजगारी से निपटने की ठोस रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लिए आप सरकार को 50 अंक दे सकते हैं। शेष 50 अंक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य लोगों की प्राथमिकताओं के तहत आवंटित किए जा सकते हैं। भारत तब तक एक विकसित देश नहीं बन सकता, जब तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा, खासकर स्कूली शिक्षा का दायरा निस्संदेह बहुत व्यापक है, लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब है। वास्तविकता यह है कि एक बच्चा औसत रूप से 7 से 8 साल स्कूल में बिताता है। इसके बाद भी करीब आधे बच्चे किसी भी भाषा में सरल पाठ पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। संख्यात्मक रूप से यह चुनौतीपूर्ण है। वे किसी भी कुशल नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जहां एक ही शिक्षक हैं। वहीं, कई स्कूलों में बड़े पैमाने पर कक्षाओं, शौचालयों और शिक्षा सहायकों की भारी कमी है। पुस्तकालय या प्रयोगशालाओं की तो बात ही न करें। केंद्र सरकार को राज्य सरकार को मदद देते हुए इन बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि एनईपी या एनटीए जैसे विवादास्पद संस्थानों को बढ़ावा देने में समय बर्बाद करना चाहिए।

कांग्रेस का प्रदर्शन और राहुल में बदलाव

शेखर गुप्ता

राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के पहले पूर्ण संसद सत्र में जा रहे हैं तब उनके लिए यह राहत की बात हो सकती है कि पिछले दो दशकों से उन्हें परेशान कर रहे तीन सवाल अब खत्म हो चुके हैं। पहला, क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कांग्रेस को गंभीरता से लेती है या उसे गंभीरता से लेना चाहिए? दूसरा, क्या वह राहुल गांधी को गंभीरता से लेती है या लेना चाहिए? और तीसरा, क्या कांग्रेस जैसी मृतप्राय पार्टी में नई जान फूंकी जा सकती है?

इन तीनों सवालों के जवाब मतगणना के दिन यानी 4 जून की दोपहर को मिल गए। न केवल भाजपा को अब कांग्रेस और राहुल गांधी को गंभीरता से लेना होगा बल्कि उनकी पार्टी को भी अब 2029 में सत्ता में वापसी की वास्तविक राह नजर आ रही है। कम से कम उसमें नई जान नजर आ रही है और वह दोबारा लड़ने को तैयार दिख रही है। सोमवार को मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही आपको यह दिखने भी लगेगा।

इस सत्र में केंद्रीय बजट का तड़का भी लगेगा। नए उत्साह से भरी कांग्रेस क्या अंतर लाएगी यह शेष विपक्ष के आचरण से भी स्पष्ट हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस में जो आलेख लिखा था वह पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात यह कहकर शुरू की कि संसद स्थगित होने का अधिक फायदा आखिर किसे होता है। जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष को। जब विपक्ष का संख्या बल कम था और उसकी बात नहीं सुनी जाती थी तब स्थगन और सदन से बहिर्गमन जैसे उपाय ही उसके पास थे। लेकिन अब वह अखाड़े में उतरकर ताल ठोकेगा।ओब्रायन की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस इतनी मजबूत वापसी नहीं करती तो क्या तृणमूल इतने जोश में होती? बिना मजबूत आधार के विपक्ष का कोई भी गठबंधन विश्वसनीय नहीं हो सकता है। कांग्रेस अभी तक यहीं नाकाम हो रही थी मगर अब हालात बदल गए हैं। जब मैं यह आलेख लिख रहा था तब मैंने अपनी टीवी स्क्रीन पर जे पी नड्?डा को देखा जो अब भी भाजपा के अध्यक्ष हैं। वह ओडिशा में बोल रहे थे और उनका भाषण कांग्रेस और गांधी परिवार पर केंद्रित था, खास तौर पर प्रियंका और राहुल गांधी की जोड़ी पर। वह उन्हें पढ़े लिखे अनपढ़ कह रहे थे। उस राज्य में कह रहे थे, जहां कांग्रेस का वजूद ही नहीं के बराबर है। नड्डा की बात से हमें राहुल के नजरिये से रखे गए तीन में से दो सवालों का जवाब मिल जाता है। भाजपा के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार की तिकड़ी मायने रखती है। तीसरे सवाल का जवाब स्वयं राहुल को देना होगा। 2004 में पहली बार सांसद बनने के बाद से उन्होंने अपनी एक राजनीतिक छवि बनाई है, जिससे उन्हें पीछा छुड़ाना होगा। यह छवि हमला करके भागने वाली राजनीति की है। इसके लिए सोशल मीडिया या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कानाफूसी वाली मशीनरी को दोष नहीं दिया जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में दो दशक का समय प्रतिष्ठा बनाने के लिए पर्याप्त है चाहे अच्छी बनाएं या खराब। 2024 के चुनावों तक वह ऊहापोह के शिकार लगते थे। अगर वह हालिया सफलता के बाद इसे पीछे छोड़ देते हैं तो न केवल उनकी प्रतिष्ठा बदल जाएगी बल्कि सबसे अहम सवाल का जवाब भी मिल जाएगा- क्या कांग्रेस के पास सत्ता में वापसी का मौका है?

राहुल के पास ढाई बड़ी सफलताएं हैं। 2009 में लोक सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 21 सीट जिताकर उन्होंने अपनी पार्टी में नई जान फूंक दी थी। जीतने वाले लगभग सभी उम्मीदवार उनके चुने हुए थे। दूसरी कामयाबी 2018 के जाड़ों में मिली जब पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कामयाबी मिली। आधी कामयाबी 2017 के गुजरात विधानसभा में मिली जब कांग्रेस ने भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। उन चुनावों में विभिन्न जातियों के युवा और बागी नेताओं ने कांग्रेस का साथ दिया था, जिसने भाजपा को वाकई में डरा दिया था। पार्टी को अपने प्रदेश में सत्ता में बनाए रखने के लिए खुद मोदी को मैदान में उतरकर भारीभरकम प्रचार अभियान चलाना पड़ा था। यह चुनाव कितना कांटे का था और यह जीत उनके लिए क्या मायने रखती थी, इसे परिणामों के बाद उनके भाषण से समझा जा सकता है। कैमरों ने उनकी आंखों में आंसुओं की झलक कैद की, जो आम तौर पर नहीं दिखते। मैंने 29 दिसंबर, 2017 को इसी स्तंभ में इस बात का जिक्र भी किया था।

अहम बात यह है कि राहुल ने इन तमाम सफलताओं का फायदा उठाकर आगे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश नहीं की। 2009 के चुनाव के बाद हमने उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर असंतुष्ट बनते देखा। उन्होंने सजायाफ्ता राजनेताओं के बारे में अपनी ही सरकार का लाया अध्यादेश सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। हालांकि बाद के कई साक्षात्कारों में उन्होंने अपनी इस हरकत पर खेद भी जताया।

दिसंबर 2018 में राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद भी उन्होंने गठबंधन करने या पार्टी में नई जान फूंकने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह भटके हुए दिखे। 2017 के गुजरात के विधानसभा चुनाव के बाद भी ऐसा ही हुआ। इनमें से हर लम्हा उनकी राजनीति का अहम मोड़ साबित हो सकता था।

यही वजह है कि हालिया आम चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी उनके समर्थकों के मन में शंका है। इस आशंका से ही उनके प्रतिद्वंद्वियों को उम्मीद है कि काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद राहुल एक बार फिर रुचि खो देंगे, गायब हो जाएंगे।

परंतु अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वह राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, सार्वजनिक बहसों में दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे हैं। यह अहम बदलाव है। इससे उनकी पार्टी में उम्मीद जगेगी। हो सकता है कि मोदी को बहुमत के आंकड़े से नीचे रोक लेने की उपलब्धि ही उन्हें आगे के लिए प्रेरित करे और मोर्चे पर लगाए रखे। यह भी हो सकता है कि मोदी, पराजय, शर्मिंदगी, अपमान और मखौल भरे एक दशक ने और उनकी पार्टी तथा उसके मुख्य लोगों को 'एजेंसियों' द्वारा निशाना बनाए जाने ने उन्हें बदल दिया हो। अगर वह इसी तरह डटे रहते हैं तो तीसरे सवाल का जवाब भी मिल जाता है। कांग्रेस वाकई सत्ता में वापसी की उम्मीद कर सकती है। यहां मैं आपको राहुल पर लिखे गए दो आलेखों की याद दिलाऊंगा, जो एक दशक के अंतराल पर आए थे। पहला आलेख 6 अप्रैल 2013 को तब लिखा गया था, जब वह कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे और उन्होंने जयपुर में 'सत्ता जहर है' का मशहूर भाषण दिया था। इसमें हमने उनकी राजनीति की तीन खामियां बताई थीं। इनमें से पहली दो का संबंध भारत की असमानता और आकांक्षाओं के बारे में उनकी गलत समझ से था। तीसरी खामी सत्ता को जहर कहने की उनकी मान्यता थी। लोकतंत्र में सत्ता जहर नहीं होती। यह अद्भुत उपहार है, सम्मान है, जो मतदाता आपको देते हैं। मैंने तब लिखा था कि सत्ता को जहर कहना सामंती सोच है, लोकतांत्रिक नहीं।

दूसरा आलेख मैंने 24 दिसंबर, 2022 को लिखा था, जब वह भारत जोड़ो यात्रा पर थे और उसमें भी कुछ सवाल उठाए गए थे। तब हमने लिखा था कि उन्हें लोगों के हुजूम से घिरना, भीड़ और स्वीकार्यता बढ़ना पहले से ज्यादा पसंद आ रहा है। वह विचारधारा पर अभियान खड़ा कर रहे थे- भारत जोड़ो बनाम भारत तोड़ो, प्रेम बनाम घृणा, धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिक, गांधी बनाम सावरकर और ऐसा लग रहा था वे इनका लुत्फ ले रहे हैं।

यहां हमने दो और प्रश्न उठाए। पहला, कांग्रेस क्या चाहती है? इसका जवाब आसान था- सत्ता। दूसरा प्रश्न थोड़ा दिलचस्प था- राहुल गांधी क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं, जो उनकी पार्टी चाहती है? अगर ऐसा है तो क्या सत्ता को जहर कहने का उनका विचार बदल गया है? क्या एक दशक तक वनवास और उपहास झेलने के बाद उन्हें सत्ता के लाभ समझ आ गए हैं? अगर इसका उत्तर हां है तभी कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद कर सकती है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

नारद, वामन, ब्रह्माण्ड, कौर्म और भागवत?

गतांक से आगे...

उपपुराणों में- नारदोक्त, वामन और ब्रह्माण्ड नाम के उपपुराण गिने गये हैं। इसी प्रकार औपपुराणों में बृहन्नारद, कौम्म और भागवत नाम के औपपुराणों की गणना है, जिसे देखकर शङ्का-पङ्क-निमग्न महाशय, उपर्युक्त रीति से महापुराणों की अष्टादश संख्या पर आक्षेप किया करते हैं। परन्तु उन्हें यह मालूम नहीं कि वाल्मीकि, तुलसीदास, और राधेश्याम आदि कवियों ने अपनी 2 राम चरित सम्बन्धी कृति को समान रूप से रामायण नाम ही दिया है; आगे भी अन्यान्य कवि यह नाम रख सकते हैं परन्तु ग्रन्थों का सन्मान कृति की विशिष्टता के अनुकूल ही होगा।

इसी प्रकार वेदव्यास जी का अनुकरण करते हुए दूसरे ऋषियों ने भी यदि प्रतिपाद्य विषय की समानता के कारण अपने निर्माण किये ग्रन्थों के नाम वामन, कौर्म, भागवत और ब्रह्माण्ड आदि रख दिये तो इसमें अनर्थ कौनसा हो गया ? तथा कृति की उत्कृष्टता और सामान्यता के तारतम्य से उन 2 ग्रन्थों को यदि महापुराण उपपुराण या औप- पुराण नामक किसी एक श्रेणी में स्थान दिया तो इसनें क्या शङ्का का पहाड़ टूट पड़ा ?

इसी तरह नारद जी के उपदिष्ट तत्त्वों को यदि व्यास ग्रादि ऋषियों ने अपनी 2 शैली में तीन भांति से निबद्ध किया हो और वे तीनों ग्रन्थ विषय उत्कृष्टता के तारतम्य से एक महापुराण श्रेणी में, दूसरा उपपुराण श्रेणी में और तीसरा औपपुराण श्रेणी में परिगणित हुआ हो तो इसमें भी आश्चर्य की बात कौन सी है ? इस प्रकार हम पुराणों की निश्चित अठारह संख्या को न्यूनाधिक बताने वाले समालोचकों या दुरालोचकों के दिये हुये हेत्वाभासों की निस्सारता दिखाने के बाद पुन: एक बार सिंहनाद से घोषित कर देते हैं कि पुराणों की संख्या न न्यून है, न अधिक है, किन्तु पूरी नौ दूनी अठारह है ।

क्रमश: ...

स्वराज के महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

मृत्युंजय दीक्षित

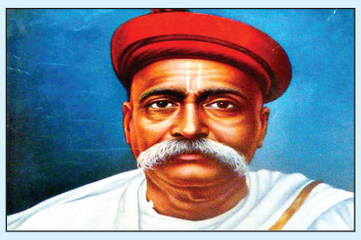

भारत की गुलामी के दौरान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोकमान्य तिलक ने देश को स्वतंत्र कराने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। वे जनसेवा में त्रिकालदर्शी, सर्वव्यापी परमात्मा की झलक देखते थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा के उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्थान स्वराज के पथगामियों में अग्रणीय है। उनका महामंत्र देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी तीव्रता के साथ गूंजा और एक अमर संदेश बन गया।

यह एक अद्भुत संयोग है कि तिलक 1856 के विद्रोह के वर्ष में तब उत्पन्न हुए जब देश का सामान्य वातावरण अंग्रेजी राज्य के विरूद्ध विद्रोह की भावना से पूर्ण था। महानायक तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को शिवाजी की कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के रत्नागिरि नामक स्थान पर हुआ। तिलक का वास्तविक नाम केशव था। तिलक को बचपन में बाल या बलवंत राव के नाम से पुकारा जाता था।

लोकमान्य तिलक का जब राजनैतिक पर्दापण हुआ तब देश में राजनैतिक अंधकार छाया हुआ था। दमन और अत्याचारों के काले मेघों से देश आच्छादित था। जनसाधारण में इतना दासत्व उत्पन्न हो गया था कि स्वराज और स्वतंत्रता का ध्यान तक उनके मस्तिष्क में नहीं था। उस वक्त आम जनता में इतना साहस नहीं था कि वह अपने मुंह से स्वराज का नाम निकाले। ऐसे कठिन समय में लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता के युद्ध की बागडोर संभाली।

सन 1891 में उन्होंने केसरी और मराठा दोनों ही पत्रों का संपूर्ण भार स्वयं खरीदकर अब इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करना शुरू कर दिया। अपनी प्रतिभा लगन और अदम्य कार्यशक्ति के बल पर शीघ्र ही जनक्षेत्र में अपना स्थान बना लिया। उनकी लौह लेखनी से ही केसरी और मराठा महाराष्ट्र के प्रतिनिधि पत्र बन गये। केसरी के माध्यम से समाज में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तिलक को राजद्रोही घोषित कर 6 वर्ष का कालापनी और एक हजार रुपये का अर्थदंड उनको दिया गया। इस दंड से सारे देश में क्रोध की लहर दौड़ गयी जनता द्वारा सरकार का विरोध किया गया बाद में सरकार ने थोड़ा झुकते हुए उन्हें साधारण सजा सुनायी। उन्हें कुछ दिन बाद अहमदाबाद तथा बाद में बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया।

जब तिलक को सजा सुनायी जा रही थी उस समय भी उनके मन में घबराहट नहीं हुई। उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि यद्यपि ज्यूरी ने मेरे खिलाफ राय दी है फिर भी मैं निर्दोष हूं। वस्तुत: मनुष्य की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली दैवी शक्ति है। वही प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के भविष्य की नियंत्रणकर्ता है। हो सकता है कि देश की यही इच्छा हो कि स्वतंत्र रहने के बजाय कारागार में रहकर कष्ट उठाने से ही मेरे अभिष्ट कार्य की सिद्धि में अधिक योग मिले।

अराजकता के किले बनते ब्रिटिश शहर

शिवकांत

सत्ता में आने के दूसरे ही हफ्ते में दो शहरों में हुए दंगों ने प्रधानमंत्री किएर स्टामर की लेबर सरकार को झकझोर दिया है। पिछले गुरुवार की शाम को इंग्लैंड के उत्तरी शहर लीड्स के हेयरहिल्स और पूर्वी लंदन के वाइटचैपल इलाके में लगभग एक साथ दंगे हुए। पर न दोनों में कोई आपसी संबंध था और न ही किसी को गंभीर चोट आयी। गृह मंत्री इवेट कूपर ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों को कानून की पूरी ताकत दिखायी जायेगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस को जांच में सरकार का पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। कभी अपने ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहे लीड्स में हुए दंगे का कारण हेयरहिल्स इलाके में रहने वाला रोमा खानाबदोश परिवार था।

परिवार के चार बच्चों में से एक की पिटाई का वीडियो किसी पड़ोसी ने शहर की बाल कल्याण एजेंसी को भेज दिया था। बच्चों को पीटना ब्रिटेन में गंभीर अपराध माना जाता है। इसलिए एजेंसी ने पुलिस बुलाकर बच्चों को बाल कल्याण केंद्र ले जाने की कोशिश की। बच्चों के परिवार ने झगड़ना शुरू किया और उनके हिमायतियों की भीड़ जुटने लगी। पुलिसकर्मियों ने बच्चों को खींचकर वैन में डालने की कोशिश की। टिक-टॉक पर इनके वीडियो देखकर उत्तेजित हुई भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना और बोतल बम फेंकना शुरू कर दिया। हेयरहिल्स के मुस्लिम नगर पार्षद ने ढाल बनकर पुलिसकर्मियों को भीड़ से बचाया।

पुलिस और दंगाइयों के झगड़े को देखकर लगभग दो हजार की भीड़ जमा हो गयी थी, जिसने पथराव, तोड़-फोड़ और आगजनी की। मुठभेड़ और हिंसा के डर से न दमकल आयी और न पुलिस। पुलिस आधी रात को आ सकी और स्थिति को काबू

में लिया। गनीमत रही कि कई घंटे चले इस दंगे में कोई हताहत नहीं हुआ। दंगा हेयरहिल्स के रोमा समुदाय के लोगों ने शुरू किया था, पर बाद में पुलिस पर अपना रोष निकालने के लिए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी समुदाय के नकाबपोश दंगाई भी इसमें शामिल हो गये थे। अभी तक आधा दर्जन लोग पकड़े गये हैं। हेयरहिल्स की आबादी करीब 31 हजार है, जिसमें से लगभग आधे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मूल के हैं और पांच हजार रोमा भी हैं, जो मानते हैं कि पुलिस उन्हें जान-बूझकर निशाना बनाती रही है। लीड्स नगर परिषद का कहना है कि गुरुवार का दंगा हेयरहिल्स और लीड्स के सामुदायिक चरित्र की पहचान नहीं है। पर वास्तविकता उतनी भली नहीं है।

तीन साल पहले इसी इलाके में रोड टैक्स डिस्क की चोरी के संदेह में बांग्लादेशी मूल के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरोध में दंगे भड़क उठे थे, जिनमें पुलिस पर हमले हुए थे और 25 कारें जला दी गयी थीं। इस घटना से बीस साल पहले मैनचेस्टर के उपनगर ऑल्डहैम में नस्लवादी दंगे हुए थे, जो ब्रैडफर्ड, लीड्स और बर्नली जैसे शहरों में भी फैल गये थे। उन दिनों भी ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार ही थी। दो साल पहले मध्य इंग्लैंड के लेस्टर में एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान पर भारत की जीत के जलूस को लेकर दंगे भड़के थे और दंगाई जिहादी गुटों और वामपंथी मीडिया ने इन दंगों का दोष भारत की मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विभाजक नीतियों के प्रभाव पर मढ़ने की कोशिश की थी। कुछ वैसा ही पिछले गुरुवार की शाम को पूर्वी लंदन के बांग्लादेशी बहुल इलाके वाइटचैपल में हुआ।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हो रहे हिंसक छात्र प्रदर्शनों और दंगों में हिंसा और मौतें ढाका में हो रही थीं, पर उन्हें लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत और दंगे पूर्वी लंदन में शुरू हो गये। शेख हसीना सरकार के विरोध और समर्थन में निकले सैंकड़ों प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गये। जब पुलिस ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, तो वे मिलकर पुलिस पर टूट पड़े। इसमें दो पुलिसकर्मी घायल हुए और कई कारों को नुकसान पहुंचा। एक व्यक्ति को दंगाई गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही प्रदर्शन सुनक सरकार और नयी लेबर सरकार की गाजा नीति के विरोध में भी हुए थे, जिनका असर हालिया संसदीय चुनाव में लगभग एक दर्जन सीटों में दिखा।

राजनीतिक हिंसा पर ब्रिटिश सरकार के सलाहकार लॉर्ड वॉलनी ने चेतावनी दी है कि राजनीति में पल रहे जहरीले और खतरनाक वातावरण में किसी नेता की हत्या का खतरा बढ़ रहा है। वॉलनी ने बताया कि ब्रिटेन में भी कुछ प्रचार गुट जीत के लिए अमेरिका जैसी ही नफरती और विरोधी का दानवीकरण करने वाली राजनीतिक भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। कुछ दिन पहले संसद के सभापति सर लिंडसे होएल ने भी कुछ सांसदों को मिली धमकियों और उनके दफ्तरों पर हुए हमलों को लेकर चिंता जतायी थी। लेस्टर, ब्लैकबर्न, बरमिंघम और पूर्वी लंदन के कुछ संसदीय क्षेत्रों में लेबर पार्टी उम्मीदवारों पर गाजा समर्थक उम्मीदवारों के समर्थन में दौड़ से हट जाने के दबाव भी डाले गये थे।

उनके प्रचार कार्यालयों पर तोड़-फोड़ हुई, नकाबपोश गुंडों ने चुनाव रैलियों में रुकावट डालीं, टायर पंक्चर किये और जान की धमकियां भी दी गयीं। महिला उम्मीदवार अधिक निशाने पर रहीं। जिन संसदीय क्षेत्रों में डराने धमकाने की कोशिशें हुईं, वहां गाजा समर्थक जिहादियों या वामपंथियों का प्रभाव अधिक था। इसलिए लॉर्ड वॉलनी ने गृह मंत्री इवेट कूपर और सुरक्षा मंत्री डैन जारविस से त्वरित जांच कर यह पता लगाने की सलाह दी है कि विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में दबाव डालने वाले गुटों के बीच कहीं कोई आपसी तालमेल तो नहीं था।

लॉर्ड वॉलनी ने कहा कि राजनीतिक गुटों का अपनी विचारधारा और नीतियों को ब्लैकमेल और आतंक के जरिये प्रतिनिधियों पर थोपना लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए घातक है। विडंबना यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में धीरे-धीरे अब यही हो रहा है। कर्ज में डूबती सरकारें जहां भी सुधार की कोशिश करती हैं, उसी क्षेत्र के राजनीतिक गुट हिंसक विरोध पर उतर आते हैं। बड़े शहरों के बाहर और भीतर ऐसे किलेनुमा अराजक क्षेत्र बन गये हैं, जहां उन्हीं समुदायों और गुटों के कायदे-कानून चलते हैं, जो वहां रहते हैं। फ्रांस में इन्हें बांल्यू कहते हैं। ब्रिटेन में नो-गो या अगम्य क्षेत्र कहते हैं। पुलिस भी वहां जाने से कतराती है। लीड्स, ब्रैडफर्ड, ऑल्डहैम, बरमिंघम और पूर्वी लंदन में ऐसे कई इलाके हैं। ये वे शेर हैं, जिनकी सवारी से लेबर पार्टी ने प्रचंड बहुमत तो हासिल कर लिया है, पर इनकी मांगें करना और इन पर काबू रख पाना कड़ी चुनौती साबित होगा।

आज का इतिहास

1802 जीए लांग ने वियतनाम के अपने एकीकरण को पूरा करने के लिए हनोई पर कब्जा किया।
1808 फ्रेंच जनरल ड्यूपॉन्ट बेलेन की लड़ाई के बाद स्पेनिश अनियमित ताकतों को आत्मसमर्पण कर दिया।
1864 अटलांटा की लड़ाई में अमेरिकी नागरिक युद्ध-संघर्ष बलों ने असफल रूप से संघ के सैनिकों पर हमला किया।
1873 सर बेंजामिन पाइन नताल के कॉलोनी के लेफ्टिनेंट - गवर्नर बनाये गए।
1894 दुनिया के पहले ऑटोरेस में पहले स्थान पर रहने के बावजूद, जूल्स-अल्बर्ट डी डायन को जीत नहीं मिली, क्योंकि उनकी भाप से चलने वाली कार नियमों से अलग थी।
1905 टाफ्ट-कत्सुरु गुप्त समझौता हुआ।
1933 विली पोस्ट, न्यूयॉर्क शहर के फ्लोयड बेनेट फील्डिन ब्रूकलिन में सात दिन, उन्नीस घंटे की उड़ान के बाद उतरने वाला, दुनिया भर में एकल उड़ान भरने वाला पहला पायलट बन गया।
1934 बैंक लुटेरा जॉन डिलिंगर (चित्र), जिसके कारनामे पूरे अमेरिका में हुए, शिकागो में जीवनी थियेटर के बाहर पुलिस की गोली से मारे गए।
1944 पोलिश सरकार के निर्वासन के विरोध में, नेशनल लिबरेशन की पोलिश समिति ने अपने घोषणापत्र को प्रकाशित किया, जिसमें विदेशी सुधारों, नाजी जर्मनी के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने का सिलसिला, उद्योग का राष्ट्रीयकरण, और पश्चिम में एक सभ्य सीमा शामिल थी। ।
1964 अफ्रीकी एकता संगठन की दूसरी बैठक आयोजित की गयी।
1975 स्टेनली फॉर्मन ने फोटो फायर एस्केप कॉम्प्लेक्शन लिया, जो स्पॉट न्यूज़ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार और वर्ष का वर्ल्डवर्ल्ड प्रेस फोटो शीर्षक था।
1991 अमेरिकी सीरियल किलर जेफरी डेमर को विस्कॉन्सिन के विल्वायूकी में गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उसके बक्से में मानव अवशेषों की खोज की।
1992 कोलम्बियाई ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार अपनी आलीशान जेल से भाग गया और अगले 17 महीने रन पर बिताए।
1993 1993 की महान बाढ़ के दौरान (बाढ़ का चित्रण), केस्कस्किया, इलिनोइस, अमेरिका के पास, टूट गया, पूरे शहर को सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा संचालित बजारों को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया।

हरियाणा में होगा सुपरहिट चुनावी मुकाबला

राज कुमार सिंह

हरियाणा में सत्ता के लिए चुनावी लड़ाई तो अक्टूबर में होगी, लेकिन इसकी खातिर जुबानी जंग और दांव-पेच शुरू हो चुके हैं। 2014 के लोकसभा की दस में से नौ सीटें जीतने के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने पहली बार हरियाणा में सरकार बनाई थी। वह भी अकेलेदम बहुमत हासिल कर, वरना तो राज्य में हमेशा वह देवीलाल और बंसीलाल के दलों की बैसाखी ही बनती रही।

2019 में भी भाजपा लोकसभा की सभी दस सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई। तब उसे देवीलाल परिवार के ही एक धड़े द्वारा नवगठित दल जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) से गठबंधन करना पड़ा था। अप्रत्याशित रूप से चुनाव में जेजेपी को 10 सीटें मिली थीं और इस समर्थन की एवज में भाजपा को दुष्यंत चौटाला को उप-मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था।

अब जबकि हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा दस में से पांच सीटें ही जीत पाई है, विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं। पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र की सुरक्षित समझी जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट भी हार चुकी कांग्रेस इस बार पांच सीटें जीत गई। कुरुक्षेत्र सीट गठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ने के कारण कांग्रेस नौ सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी।

जाहिर है, इस सफलता के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस, खासकर हुड्डा खेमे के तेवरों से तो लगता है कि वे सत्ता में वापसी तय मानकर चल रहे हैं, लेकिन चुनावी रण इतना आसान भी नहीं होता। 2019 में भी कांग्रेस ने ऐसे ही तेवरों के साथ विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। गुटबाजी से ग्रस्त कांग्रेस की एकता की तस्वीर पेश करने के लिए आलाकमान ने पार्टी छोड़ गए अशोक तंवर की जगह कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो किरण चौधरी की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने।

वैसे, 2014 विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने आईएनएलडी (इनेलो) को मुख्य विपक्षी दल बनाया था और अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष बने थे, लेकिन पार्टी में

मची भगदड़ के बाद स्थितियां बदल गईं। बेशक 2014 के मुकाबले कांग्रेस ने 2019 में भाजपा को जोरदार टक्कर दी, लेकिन उससे नौ सीटें कम हासिल कर पाई। भाजपा की छह सीटें कम करने पर अपनी पीठ थपथपाते हुए हुड्डा खेमे ने सफाई दी कि दूसरे गुटों के दबाव में गलत टिकट बंटवारे के कारण पार्टी सरकार बनाने से चूक गई, जबकि विरोधी गुट ने यही आरोप हुड्डा खेमे पर लगाया।

सवाल यह है कि 2019 के मुकाबले 2024 में हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य कितना बदला हुआ है? पहला बड़ा बदलाव तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन है। दूसरा यह कि भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ये बदलाव कांग्रेस के लिए सकारात्मक कहे जा सकते हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी का पार्टी छोड़ना अच्छी खबर नहीं है। कुलदीप पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं तो किरण एक और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू। दोनों ने हुड्डा खेमे के चलते कांग्रेस छोड़ी। यह कहना आसान है कि किसी के आने-जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कड़े मुकाबले में छोटी-छोटी चीजें भी बड़ा असर डालती हैं।

भाजपा में भी काफी कुछ बदला है। 2014 में बहुमत मिलने पर मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद के लिए आलाकमान की चौंकाने वाली पसंद थे, लेकिन 2019 में वह स्वाभाविक पसंद बने। कई परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाबाशी पाने वाले मनोहर लाल ने नौ साल से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद स्वयं ही इस साल मार्च में पद छोड़ दिया। करनाल से लोकसभा चुनाव जीतकर अब वह मोदी सरकार में आवास, शहरी विकास और ऊर्जा सरीखे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व संभाल रहे हैं।

वहीं, उनके उत्तराधिकारी के जरिये भाजपा ने विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछा दी है। पिछली लोकसभा में कुरुक्षेत्र से सांसद रहे नायब सिंह सैनी को पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर मुख्यमंत्री। यह पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए किया गया। कुछ ही दिन पहले राई के विधायक मोहन लाल बड़ौली को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बेशक बड़ौली हाल ही में सोनीपत से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनकी ताजपोशी का संकेत साफ है कि भाजपा फिर जाट-गैर जाट के आजमाए हुए समीकरण पर चुनाव लड़ने जा रही है।

ऐसा नहीं कि भाजपा को इस बार कड़े चुनावी मुकाबले का आभास नहीं है। विपक्ष का मुख्य मुद्दा बनी अग्निपथ योजना के अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार की कुछ सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण और अन्य सेवाओं में आयु सीमा में छूट समेत युद्धस्तर पर लोक-लुभावन योजनाओं की घोषणा दरअसल चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा है। केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद हरियाणा की सत्ता में भाजपा की हैट्रिक को एकमात्र लक्ष्य बनाने वाले मनोहर लाल की भी इसमें बड़ी भूमिका बताई जाती है।

असल में, राज्य में संभावित बहुकोणीय मुकाबला भाजपा की राह आसान बना सकता है। लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसने किसी से भी गठबंधन करने से मना कर दिया है। अब आप अकेले लड़ेगी या 2019 लोकसभा चुनाव की दोस्त जेजेपी से हाथ मिलाएगी, यह तो देखना होगा। लेकिन आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन करने से त्रिकोणीय मुकाबला तो तय हो गया है। आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इस अलायंस का जो भी असर हो, लेकिन इसे, जेजेपी और आप को मिलने वाले वोट होंगे सत्ता विरोधी ही। यानी सत्ता विरोधी वोटों के बंटने का लाभ भाजपा को ही मिलेगा।

पाकिस्तान से दूरी बनाता चीन?

आरके सिन्हा

पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देता रहा है। मुंबई में 2008 में हुए हमलों से लेकर कठुआ, पठानकोट और उरी वगैरह में उसने आतंक फैलाया है। पर अब पाकिस्तान खुद ही अपने आतंकवाद की आग में स्वाहा हो रहा है। वह भयभीत है। डर का कारण चीन का नाराज होना है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के मारे जाने के कारण चीन सरकार उससे सख्त नाराज है। इसलिए सारे पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को अब खास सुरक्षा दी जा रही है, जो पाकिस्तान में चीन की मदद से चल रही परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में एक नया पुलिस बल भी बनाया गया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीनी वित्त पोषित मेगा परियोजनाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें काम करने वाले चीनियों को आतंकवादी चुन-चुन कर मार रहे हैं। इन हमलों के कारण ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं खतरे में हैं। चीन ने पाकिस्तान में अपना बड़े स्तर पर निवेश करना 2015 में शुरू किया था। चीन की योजना थी कि वह पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर का निवेश विभिन्न परियोजनाओं में करे। इस वक्त हजारों चीनी कामगार और इंजीनियर पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका से मदद मिलनी बंद हो गई थी। इसलिए उसे चीनी निवेश का ही एकमात्र सहारा था। उस पर भी फिलहाल तो ग्रहण लग गया दिखता है। पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान में आतंकवादी समूह फिर से उभरे हैं। इस दौरान आतंकवादी हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका असर चीनी परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा हुआ है। इस कारण चीन से पोषित परियोजनाओं पर काम ठंडा पड़ने लगा है। मार्च के महीने के अंत में, सशस्त्र आतंकियों ने अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित ग्वादर में चीन निर्मित और संचालित बंदरगाह को निशाना बनाया, जिसमें दो पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद आतंकवादियों ने देश के दूसरे सबसे बड़े एयर बेस पर हमला किया। यह बलूचिस्तान में है। यहां भी चीनी नागरिक सक्रिय थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक जलविद्युत परियोजना पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें पांच चीनियों की मौत हो गई। इसके बाद चीनी कंपनियों ने कम से कम तीन महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं पर अपना काम रोक दिया था। ये परियोजनाए थीं- दासू बांध, डायमर-बाशा बांध और तारबेला पांचवां एक्सटेंशन। खैबर पख्तूनख्वा सीमांत गांधी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। चीनियों पर हमले खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर अखबार दि डॉन में 1 अप्रैल, 2024 को छपी एक खबर के अनुसार, इस साल के पहले तीन महीनों में देश के दो प्रमुख राज्यों क्रमश: खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बीते साल की इसी अवधि की तुलना में आतंकी और हिंसक वारदातों में 92 और 86 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। जाहिर है, अपने नागरिकों पर हमले के कारण चीन नाराज है। पाकिस्तान चीन को अपना सबसे भरोसे का मित्र कहता है। चीन के नाराज होने से पाकिस्तान की सांसें रुक रही हैं। पाकिस्तान से मिल रही खबरों पर यकीन करें तो चीनी नागरिक अपनी जान को खतरा होने के कारण पाकिस्तान छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार बार-बार अपराधियों को पकड़ने का वादा कर रही है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है।

मनोज जरांगे जैसे नहीं बन पा रहे ओवैसी

अमिताभ श्रीवास्तव

पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से बहुत प्रभावित दिखे। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में जरांगे को मुबारकबाद देते हुए यह तक कहा कि जरांगे अपने समाज के लिए खड़े हुए और उनकी वजह से ही आठ मराठा उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में कामयाब हुए। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि मगर मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? मुस्लिम समाज को भी अपने अधिकारों के लिए इसी तरह लड़ना होगा।

अब सवाल यह है कि मनोज जरांगे मात्र दस-ग्यारह महीने में इस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं कि राजनीति उनके इर्द-गिर्द घूमने लगी है। चुनाव की हार-जीत का फैसला उनके नाम पर लिखा जाने लगा है। वहीं करीब सवा दशक से महाराष्ट्र की राजनीति में अपने कदम जमाने की कोशिश में लगे ओवैसी को बार-बार दो कदम आगे और दो कदम पीछे होना पड़ रहा है। लोकसभा से लेकर नगर पालिका तक उनके खाते में जो आज होता है, वह कल नहीं होता है।

मूल रूप से हैदराबाद की पार्टी के रूप में पहचान रखने वाली एआईएमआईएम ने बरास्ता नांदेड़ महानगर पालिका के चुनाव जीत महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखा था। उसने वर्ष 2012 के नांदेड़ मनपा चुनाव में 11 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। मगर पांच साल बाद वर्ष 2017 में हुए मनपा के चुनाव में वह एक भी सीट बचाने में विफल रही। इस चुनाव को एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी(बसपा) के साथ गठबंधन कर लड़ा था।

बावजूद इसके पार्टी बहुत जल्द ही नांदेड़ में मुसलमानों के बीच अप्रासंगिक नजर आई और कांग्रेस ने उससे सारी सीटें जीत लीं। हालांकि वर्ष 2012 में नांदेड़ में जीत से उत्साहित एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में विस्तार करने का

निर्णय लिया था। उसे दूसरी सफलता वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में मिली, जिसमें उसने तत्कालीन औरंगाबाद और मुंबई की एक सीट जीती। इसी क्रम में उसने मुंबई, सोलापुर और तत्कालीन औरंगाबाद सहित राज्य के अन्य शहरों में निकाय चुनाव लड़े, जहां उसे अपना खाता खोलने में सफलता मिली। यहां तक कि तत्कालीन औरंगाबाद महानगर पालिका में उसे 25 सीटें पाने में सफलता मिली।

कुल मिलाकर तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र ही एकमात्र ऐसा राज्य रहा, जहां एआईएमआईएम को अच्छा समर्थन मिला और दूसरे राज्यों की तुलना में यहां बेहतर स्थिति रही। इस दौरान वर्ष 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव में उसका कोई प्रभाव दर्ज नहीं हुआ। उसे सीमांचल की छह सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़कर सभी पर हार का सामना करना पड़ा। किंतु वर्ष 2020 में उसे पांच सीटों पर विजय मिली, हालांकि वे ज्यादा समय तक उसके खाते में नहीं रहीं। वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वह सभी 38 सीटें हार गई। ऐसा ही हाल दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी 50 सीटों पर चुनावी हार के रूप में सामने आया। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात में भी प्रयास हुए, किंतु सफलता कहीं हासिल नहीं हुई।

फिलहाल लोकसभा में एआईएमआईएम के एकमात्र सांसद के रूप में ओवैसी सदन के भीतर और बाहर पुरजोर तरीके से मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं। वह मुस्लिमों की ज्वलंत समस्याएं जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, धार्मिक आधार पर भेदभाव को उठाकर मुस्लिमों के प्रति खासी सहानुभूति भी जुटाने का काम करते हैं। वह अपनी सभाओं में काफी उत्तेजक ढंग से बात रखते हैं, जिससे युवा मुस्लिमों में उनके प्रति एक जोश पैदा होता है। वह लगातार देशभर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं और वहां की समस्याओं को राष्ट्रीय चिंता की शक्ल देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिर भी वह तेलंगाना छोड़ हर स्थान पर राजनीतिक स्तर पर मात खा जाते हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि मनोज जरांगे के सामने आने से बीड़ में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की नेता पंकजा मुंडे की शिकस्त हुई।

हालांकि वह भी औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार इम्तियाज जलील की कामयाबी के लिए पूरी शिद्दत के साथ खड़े थे। इससे पहले वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में सांसद ओवैसी के साथ तत्कालीन सांसद जलील औरंगाबाद विधानसभा सीटों के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े थे। मगर चुनाव में दो सीट पर पराजय मिली और एक सीट को हाथ से गंवाना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव में जब हार हुई है तो राजनीति के 'मीर कासिम' और 'मीर जाफर' की ओर इशारा किया जाने लगा। स्पष्ट है कि मराठा एकजुटता हर स्तर पर टूटती नहीं है, चाहे वह चुनाव की बात हो या फिर समाज की समस्याओं की हो तो फिर मुस्लिम एकता बंध कर क्यों नहीं रह पाती है। वह भी उस स्थिति में जब सांसद ओवैसी की तरह राष्ट्रीय स्तर का नेता खुले मैदान पर उतरता हो।

हालांकि, देश में 14 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 11 फीसदी मुस्लिमों की आबादी का जब जिक्र किया जाता है तो वह धार्मिक आधार पर तो एकजुट हो जाती है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा पर मुट्ठी बंधी नहीं रह पाती है। उसे अपने सही हितचिंतक को पहचानने में कोई सहायता नहीं मिलती है। उसे सामाजिक प्रभाव में अपने विचारों को ढाल कर कोई निर्णय लेना होता है।

जम्मू क्षेत्र में चौकसी बढ़ाने की जरूरत

डॉ. अमित

बीते कुछ सप्ताह से जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। इसी माह 15 दिनों में ही पांच बड़ी वारदात हुई हैं, जिनमें सुरक्षाकर्मियों समेत कई लोगों की जान गयी है। कुछ साल पहले तक आतंकी घटनाएं मुख्य रूप से कश्मीर घाटी तक सीमित थीं। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि आतंकवादी गिरोह घाटी में खुलेआम अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे और उनके समर्थन में कुछ लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी करते थे। तब जम्मू क्षेत्र में साल भर में ऐसी दो-तीन घटनाएं ही होती थीं। कुछ साल से, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद कश्मीर घाटी में बहुत हद तक शांति स्थापित करने में सफलता मिली है। लेकिन जम्मू क्षेत्र में वारदातों की संख्या बढ़ी है। निश्चित रूप से यह प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अलगाववादी और आतंकवादी संगठन मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में ही सक्रिय रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखें, तो जम्मू हिंदू-बहुल क्षेत्र है। वहां और लद्दाख में पाकिस्तान-समर्थित अलगाववाद को पैर पसारने की जगह नहीं मिल सकी। अभी तक जो जानकारियां हैं, इन आतंकी घटनाओं में शामिल आतंकी स्थानीय नहीं हैं।

सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखें, तो सुरक्षा बलों और संबंधित एजेंसियों का मुख्य ध्यान कश्मीर घाटी में रहा है, जो स्वाभाविक है। इसी तरह हमारा खुफिया तंत्र भी घाटी में ही अधिक मुस्तैद रहा है। जम्मू क्षेत्र में वैसी चौकसी और निगरानी नहीं रही है। इसका फायदा भी आतंकी गिरोह उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय से खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है और लोगों के जरिये सूचना हासिल करने की प्रक्रिया धीमी पड़ी है। बदलते समय में तकनीक का अधिक इस्तेमाल जरूरी है, पर लोगों के माध्यम से आतंकी और अलगाववादी समूहों की गतिविधियों के बारे में पता करते रहना भी जरूरी है। जो स्थिति जम्मू-कश्मीर में है, उसमें आप छोटी से छोटी सूचना की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जैसा पहले कहा गया है, आतंकवाद से लड़ने के अधिक तंत्र कश्मीर घाटी में केंद्रित हैं, लेकिन जम्मू क्षेत्र में जो स्थिति पैदा हो रही है, उसे देखते हुए अब वहां भी बहुत सतर्कता एवं निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। जम्मू क्षेत्र में तैनात सुरक्षाकर्मियों के

प्रशिक्षण पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे आतंकियों का मुकाबला प्रभावी ढंग से कर सकें।

जब 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय लिया गया, तब से ही घाटी के अलगाववादियों, आतंकवादियों तथा उनके पाकिस्तानी प्रायोजकों में एक बड़ी बेचैनी रही है। कुछ मुस्लिम राष्ट्रों ने भी कश्मीर की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया था। लेकिन हाल के वर्षों में कश्मीर घाटी में हालात तेजी से सुधरे हैं तथा आतंकी घटनाओं और अलगाववादी गतिविधियों में बड़ी कमी आयी है। यह सरकार के विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि कश्मीर में शांति बहाली से तथा विभिन्न योजनाओं से विकास में उल्लेखनीय तेजी आ रही है। निवेश भी बढ़ रहा है। जी-20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान वहां अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। पर्यटन में निरंतर वृद्धि हो रही है। युवा कश्मीरी, महिलाएं भी, शिक्षा, रोजगार, खेल आदि विभिन्न क्षेत्रों में अधिक भागीदारी कर रहे हैं।

बीते लोकसभा चुनाव में कई दशकों बाद बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने मतदान किया है। इन सबसे यही इंगित हो रहा है कि आम कश्मीरी देश के विकास की मुख्यधारा से उत्साहपूर्वक जुड़ रहा है। इससे आतंकियों में हताशा का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि आतंकी गुट कश्मीरी युवाओं को बरगलाकर आतंक से जोड़ने में विफल हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान भी बेचैन हो उठा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से कहा गया कि अगले कार्यकाल में पाक-अधिकृत कश्मीर को हासिल करने की कोशिश की जायेगी। इससे भी अलगाववादी दबाव में आ गये। इन हताशाओं का एक परिणाम हम जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं के रूप में देख रहे हैं।

जगजाहिर है कि आज जो पाकिस्तान में बदहाली है, उसका एक बड़ा कारण उसका आतंकवाद को शह देना है। पड़ोसी देशों को अस्थिर और अशांत करने की उसकी पुरानी नीति रही है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नवाज शरीफ ने कहा था कि करगिल में घुसपैठ और लड़ाई पाकिस्तान की गलती थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि ऐसा करना तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किये गये समझौते के साथ विश्वासघात था। अनेक ऐसे बयान भी वहां दिये गये हैं कि भारत से कारोबारी संबंध बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान ने बातचीत के प्रस्ताव भी भेजे हैं। हाल में यह प्रस्ताव भी आया कि दोनों देशों को द्विपक्षीय क्रिकेट खेलना चाहिए।

पर भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और द्विपक्षीय वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। बातचीत तभी संभव होगी, जब पाकिस्तान आतंकवाद को रोकेगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के अवसर पर सभी पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान को नहीं। साल 2014 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आमंत्रित थे और उसके बाद कुछ समय के लिए सकारात्मक माहौल भी बना था, पर कुछ समय बाद आतंकी घटनाओं में वृद्धि होने लगी। पाकिस्तान को अपनी ध्वस्त अर्थव्यवस्था और देश में बढ़ती अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा भारत में आतंक को प्रश्रय देने से बाज आना चाहिए। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं तथा मुख्यधारा में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं, वह उत्साहजनक है। विकास कार्यों से कश्मीर में एक नयी इबारत लिखी जा रही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश प्रशासन को अपने कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए।

इसमें राजनीतिक दलों, विशेषकर क्षेत्रीय दलों की भी सकारात्मक भूमिका हो सकती है। लोकसभा चुनाव में स्थानीय दलों को नुकसान हुआ है। उन्हें उस पर समुचित विचार करते हुए जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त कराने के प्रयासों में साथ देना चाहिए। जम्मू-कश्मीर ने हिंसा व आतंक का बहुत लंबा दौर देखा है, जो अपने अंतिम चरण में है। पाकिस्तान और आतंकी गिरोह नहीं चाहते कि राज्य में अमन-चैन हो। हालिया हमलों को देखते हुए सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बचे-खुचे आतंकियों पर जल्दी ही काबू पा लिया जायेगा।

विवादास्पद नारा लगाने वालों को बरी करने से अच्छा संदेश नहीं गया

नीरज कुमार दुबे

राजस्थान में अजमेर की एक अदालत ने 2022 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दरवाजे के सामने सर तन से जुदा के विवादास्पद नारे लगाने के आरोपी सभी छह लोगों को बरी कर दिया है। इसके पहले अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने पर हिंदुओं को अपनी हिम्मत दिखाने जैसा बयान देने के मामले में बरी हो चुके हैं। ऐसे ही कई और वाकये भी हैं जिन पर आये अदालती फैसलों से सवाल उठता है कि क्या यह भड़काऊ बयान अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं? जहां तक अजमेर दरगाह के दरवाजे पर लगाये गये विवादास्पद नारों की बात है तो उसके वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं इसलिए सवाल उठता है कि आखिर क्यों और किस आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया गया? देखा जाये तो राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार की तुष्टिकरण की नीति के चलते राज्य में कई बार हालात खराब हुए लेकिन फिर भी तत्कालीन सरकार अपनी नीति से डिगी नहीं थी। यह साफ प्रदर्शित हो रहा है कि सर तन से जुदा के खुल्लम खुल्ला नारे लगाने वाले सभी आरोपी इसलिए बरी हो गये क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में मामले की जांच ठीक से नहीं की गयी और संभवत: आरोप पत्र में खामियां रहीं। राजस्थान की वर्तमान सरकार को इस मामले की नई सिरे से जांच करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि किसके आदेश पर जांच प्रभावित की गयी और अदालत के समक्ष सभी सबूत नहीं रखे गये थे? हम आपको याद दिला दें कि साल 2022 में अजमेर दरगाह के मुख्य द्वार पर 17 जून को भीड़ के सामने सर तन से जुदा का नारा अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने लगाया था। विवाद खड़ा हुआ तो वह हैदराबाद भाग गया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर राजस्थान लाया गया था। दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती पर आरोप था कि अजमेर दरगाह के मुख्य द्वार, जिसे निजाम गेट कहा जाता है, पर 17 जून को नुपूर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की एक रैली में पुलिस की मौजूदगी में उसने भड़काऊ भाषण दिए थे। इस संबंध में एक प्राथमिकी 25 जून 2022 की रात को दर्ज की गई थी। लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की 28 जून को निर्मम हत्या की घटना हो गयी उसके बाद अजमेर पुलिस हरकत में आई और गौहर चिश्ती के साथ मौजूद फकर जमाली, रियाज और तामिज को 29 जून को गिरफ्तार किया गया। वहीं, चौथे आरोपी को 30 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने जो विवादास्पद नारे लगाये थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था उसके वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गये थे। उस समय दरगाह पुलिस थाने के एक कांस्टेबल द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को देखेंगे तो पता चलेगा कि आरोप गंभीर थे। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि गौहर चिश्ती ने धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर का उपयोग कर ''गुस्ताखी ए नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा'' के नारे लगाकर लोगों को उकसाया था। कांस्टेबल के मुताबिक भीड़ को हिंसा के लिये उकसाना और हत्या का आह्वान करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 117 (दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा जनता को अपराध के लिये उकसाना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) 34 (कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किए गये कार्य) 143 और 149 (गैर कानूनी सभा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। देखा जाये तो प्राथमिकी में आरोप गंभीर थे इसलिए मामले की अदालत में चली सुनवाई के बाद जब फैसला आया तो सभी को हैरत हुई। सरकारी वकील गुलाम नजमी फारूकी ने जब यह बताया कि अदालत ने खादिम (सेवक) गौहर चिश्ती, ताजिम सिद्दीकी, फारूक जमाली, नासिर, रियाज हसन और मोईन को बरी कर दिया है तो सवाल उठा कि भड़काऊ नारेबाजी के जो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वह जज साहब को क्या दिखाए नहीं गये? सरकारी वकील गुलाम नजमी फारूकी ने हालांकि कहा है कि अदालती आदेश की समीक्षा करने के बाद फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। इसलिए उम्मीद है कि आरोपियों को एक ना एक दिन सजा जरूर मिलेगी। लेकिन यह मामला हमारी प्रणाली में व्याप्त खामियों की ओर इशारा भी करता है। सरेआम लोगों को भड़काने वाले और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले यदि इसी तरह बरी होते रहेंगे तो अराजक तत्वों का हौसला बढ़ेगा इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में सख्ती से निबटने के लिए कड़े कानून बनाये।बहरहाल, केंद्र सरकार को यह भी देखना चाहिए कि हाल ही में जमीयत उलेमा ए हिंद के महमूद मदनी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो तुम कहीं और चले जाओ। अगर ऐसे बयान सामने आते रहे तो इससे साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचेगी। इसलिए भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का समय आ चुका है।

श्रावण मास पर रुद्र के माहात्म्य

सावन में रुद्राभिषेक की परंपरा है। शिवजी को रुद्र इसलिए कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि वे रुत अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों का नाश करते हैं। श्रावण मास पर रुद्र के माहात्म्य पर आलेख..

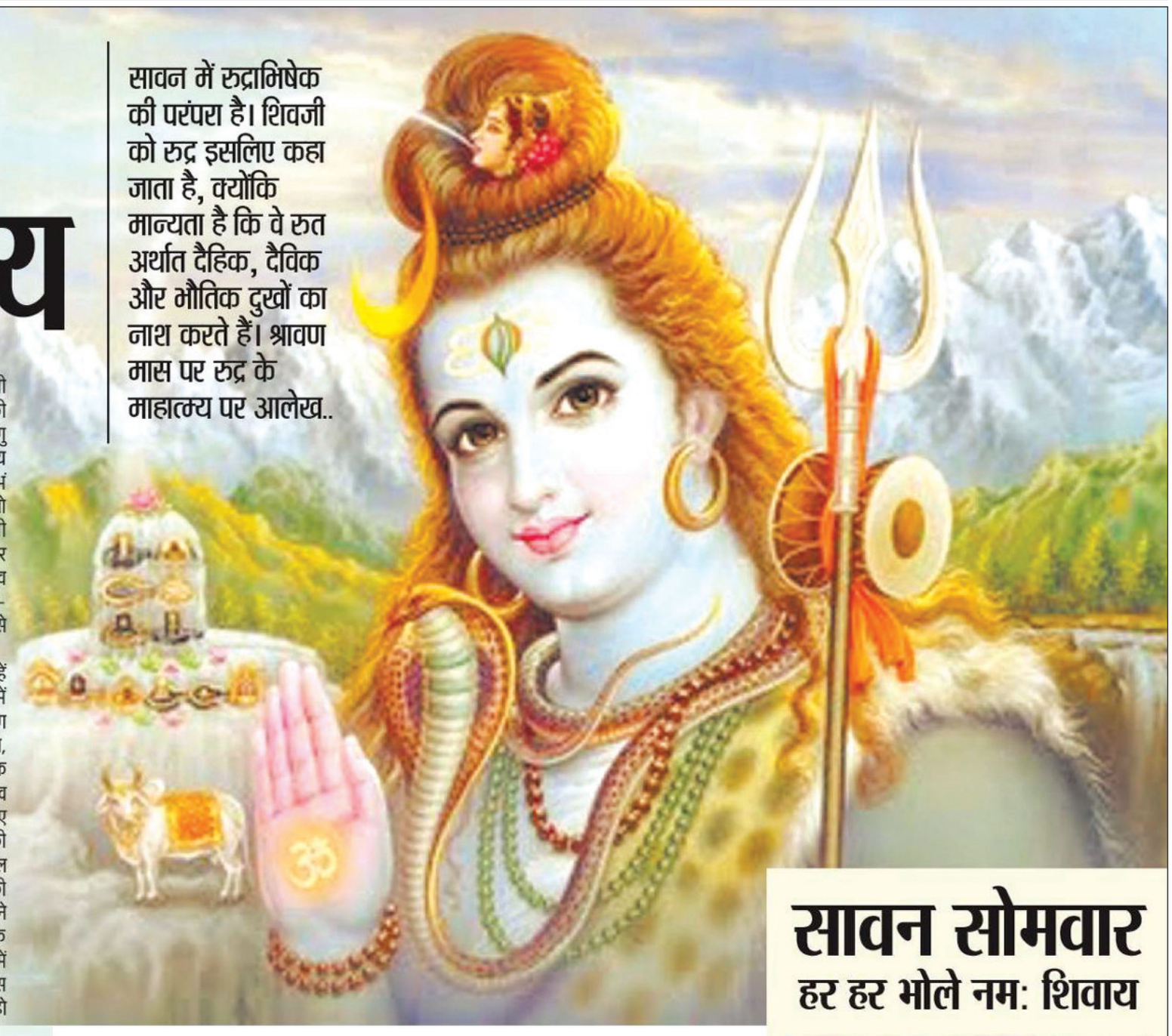

वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार, वेद- शिव- शिवो वेद- यानी वेद शिव हैं और शिव वेद हैं। अर्थात शिव वेदस्वरूप हैं। इसके साथ ही वेद को भगवान सदाशिव का निःश्वास बताते हुए उनकी स्तुति में कहा गया है - यस्य निःश्वसितं वेदायो वेदेभ्योखिलं जगत। निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्र्थ महेश्वरम।। अर्थात वेद जिनके निःश्वास हैं, जिन्होंने वेदों के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो समस्त विद्याओं के तीर्थ हैं, ऐसे देवों के देव महादेव की मैं वंदना करता हूं। सनातन संस्कृति में वेदों की तरह शिव जी को भी अनादि कहा गया है।

वेदों में साम्ब सदाशिव को रुद्र नाम से पुकारा गया है। शिवजी को रुद्र इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये रुत अर्थात दुख को दूर कर देते हैं। जो दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों का नाश करते हैं, वे रुद्र हैं। इसीलिए उन्होंने त्रिशूल धारण किया है। रुद्रहृदयोपनिषद कहता है, सर्वदेवात्मको रुद्र- अर्थात रुद्र सर्वदेवमय हैं। अथर्व शिखोपनिषद भी इसका समर्थन करता है - रुद्रो वै सर्वा देवता अर्थात रुद्र समस्त देवताओं का स्वरूप हैं। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्रोपासना का विधान मिलता है। इसमें रुद्र शब्द के सौ पर्यायवाची नामों का उल्लेख होने से इसे शतरुद्री भी कहते हैं। माना जाता है कि शतरुद्री के माहात्म्य का उपदेश महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को दिया था। श्वेताश्वतरोपनिषदके अनुसार, महाप्रलय के समय एकमात्र रुद्र ही विद्यमान रहते हैं। श्रुतियों से यह तथ्य विदित होता है कि रुद्र ही परमपुरुष यानी आदिदेव साकार बहमा हैं, जिनके द्वारा ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। ब्रहमा, विष्णु और महेश इनकी त्रिमूर्ति हैं। रुद्र का परिचय शास्त्रों में इस प्रकार भी दिया गया है - अशुभं द्रावयन् रुद्रो यज्जाहार पुनर्भवम। तत- स्मृताभिधो रुद्रशब्देनात्राभिधीयते।। अर्थात जो प्राणी जीवनकाल में सब अनिष्टों को दूर करते हैं और शरीर त्यागने पर मुक्ति प्रदान करते हैं, वे सदाशिव रुद्र के नाम से जाने जाते हैं। इसी कारण दुखों- कष्टों से मुक्ति तथा सद्गति प्राप्त करने के उद्देश्य से मनुष्य रुद्रोपासना करता आया है।

रुद्र को अभिषेकप्रिय रुद्र कहा गया है, यानी उन्हें अभिषेक पसंद है। इसीलिए सावन के महीने में रुद्र का अभिषेक किया जाता है। सामान्यतः लोग जल द्वारा अभिषेक करते हैं, तो सामर्थ्यवान दूध, दही, शहद आदि विभिन्न द्रव्यों से उनका अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को जनकल्याण के लिए पिया था, तब इंद्र ने शीतलता देने के लिए वर्षा की थी, इसी कारण श्रावण मास में शिव जी को जल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुइ। भगवान शंकर की शक्ति पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। हमने पर्वतीय क्षेत्र को जो क्षति पहुंचाई है, उसके विनाशकारी परिणाम दिखाई देते हैं। इसलिए हमें हिमालय की पवित्रता बनाए रखने का संकल्प इस सावन में लेना चाहिए, तभी शिवार्चन सफल हो सकेगा और शिव हमेशा कल्याणकारी होंगे।

सावन सोमवार
हर हर भोले नमः शिवाय

सावन और शिव का भारतीय संस्कृति से गहरा मेल है। सावन के झूलों से लेकर सावन सोमवार की बेलपत्री तक..सब कुछ मानो भावनाओं को हरा-भरा कर देने वाला। सावन के आते ही शिव भक्तों में पूजा अर्चना के लिए नई उमंग का संचार हो गया है। चारों ओर गूंजने लगे हैं बोल बम.. के जयकारे और हरे व केसरिया रंग से धरती पट सी गई है। सावन सोमवार को शिवालयों में सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहेगा। हर कोई भोले से वरदान मांगने पहुंच जाता है उनके द्वार। शास्त्रों और पुराणों का कहना है कि श्रावण मास भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। इस माह में शिवार्चना के लिए प्रमुख सामग्री बेलपत्र और धतूरा सहज सुलभ हो जाता है। सच पूछा जाए तो भगवान शिव ही ऐसे देवता है, जिनकी पूजा-अर्चना के लिए सामग्री को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। अगर कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो जल ही काफी है। भक्ति भाव के साथ जल अर्पित कीजिए और भगवान शिव प्रसन्न।

जल चढ़ाओ और जो चाहे मांग लो

शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास भगवान शकर को विशेष प्रिय है। अतः इस मास में आशुतोष भगवान शकर की पूजा का विशेष महत्व है। सोमवार शकर का प्रिय दिन है। इसलिए श्रावण सोमवार का और भी विशेष महत्व है। भगवान शकर का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मास में लघुरुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ करके प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत किया जाता है। प्रातः काल गगा या किसी पवित्र नदी सरोवर या घर पर ही विधि पूर्वक स्नान करने का विधान है। इसके बाद शिव मदिर जाकर या घर में पार्थिव मूर्ति बना कर यथा विधि से रुद्राभिषेक करना अत्यत ही फलदायी है। इस व्रत में श्रावण महात्म्य और विष्णु पुराण कथा सुनने का विशेष महत्व है।

ऐसे करें शिव को प्रसन्न

श्रावण मास में आने वाले सोमवार के दिनों में भगवान शिवजी का व्रत करना चाहिए और व्रत करने के बाद भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिवजी, माता पार्वती व नन्दी देव की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री में जल, दुध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत,मोली, वस्त्र, जनेऊ, चन्दन, रोली, चावल, फूल, बेल-पत्र, भा ग, आक-धतूरा, कमल,गट्टा, प्रसाद, पान-सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, दक्षिणा चढाया जाता है। इस दिन धूप दीया जलाकर कपूर से आरती करनी चाहिए। व्रत के दिन पूजा करने के बाद एक बार भोजन करना चाहिए। और श्रावण मास में इस माह की विशेषता का श्रवण करना चाहिए।

श्रावण मास शिव उपासना महत्व

भगवान शिव को श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस माह में प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान श्री शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मास में भक्त भगवान शकर का पूजन व अभिषेक करते है। सभी देवों में भगवान शकर के विषय में यह मान्यता प्रसिद्ध है, कि भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते है। एक छोटे से बिल्वपत्र को चढ़ाने मात्र से तीन जन्मों के पाप नष्ट होते है।

श्रावण मास के विषय में प्रसिद्ध एक पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के सोमवार व्रत, एक प्रदोष व्रत तथा और शिवरात्री का व्रत जो व्यक्ति करता है, उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रहती है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान यह व्रत फल देता है।

इस व्रत का पालन कई उद्देश्यों से किया जा सकता है। महिलाएं श्रावण के 16 सोमवार के व्रत अपने वैवाहिक जीवन की लंबी आयु और संतान की सुख-समृद्धि के लिये करती है, तो यह अविवाहित कन्याएं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से कर मनोवाछित वर की प्राप्ति करती है। सावन के 16 सोमवार के व्रत कुल वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और सुख -सम्मान के लिये किया जाता है।

शिव पूजन में बेलपत्र प्रयोग करना

भगवान शिव की पूजा जब बेलपत्र से की जाती है, तो भगवान अपने भक्त की कामना बिना कहे ही पूरी करते है. बिल्व पत्र के बारे में यह मान्यता प्रसिद्ध है, कि बेल के पेड़ को जो भक्त पानी या गंगाजल से सींचता है, उसे समस्त तीथरें की प्राप्ति होती है। वह भक्त इस लोक में सुख भोगकर, शिवलोक में प्रस्थान करता है। बिल्व पत्थर की जड़ में भगवान शिव का वास माना गया है। यह पूजन व्यक्ति को सभी तीथरें में स्नान करने का फल देता है।

सावन माह व्रत विधि

सावन के व्रत करने से व्यक्ति को सभी तीथरें के दर्शन करने से अधिक पुन्य फल प्राप्त होते है। जिस व्यक्ति को यह व्रत करना हो, व्रत के दिन प्रातः काल में शीघ्र सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। श्रावण मास में केवल भगवान श्री शकर की ही पूजा नहीं की जाती है, बल्कि भगवान शिव की परिवार सहित पूजा करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से शुरु होकर सूर्यास्त तक किया जाता है। व्रत के दिन सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। तथा व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में सूर्यास्त के बाद एक बार भोजन करना चाहिए।

प्रातःकाल में उठने के बाद स्नान और नित्यक्रियाओं से निवृत होना चाहिए। इसके बाद सारे घर की सफाई कर, पूरे घर में गंगा जल या शुद्ध जल छिड़कर, घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद घर के ईशान कोण दिशा में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति स्थापना के बाद सावन मास व्रत संकल्प लेना चाहिए।

श्रीमल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पूरी होती हैं मनोकामनाएं

दक्षिण भारत में कैलाश के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश का श्रीमल्लिकार्जुन मंदिर भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्रीसैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

श्रीमल्लिकार्जुन का पौराणिक महत्व

एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और गणेश अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किन्तु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद्द पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को पता लगी तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहां आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े लेकिन गणेशजी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था।

गणेश जी शरीर से स्थूल किन्तु बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश ने उनकी सात परिक्रमा की। इस तरह से वह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देख कर शिव और पार्वती दोनों काफी खुश हुए और उन्होंने श्रीगणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया। जब तक स्वामी कार्तिकेय सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्रीगणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था, जिनसे उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे।

यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देवर्षि नारद को भेजा गया लेकिन वह नहीं माने। कार्तिकेय के चले जाने पर माता पार्वती भी क्रौंच पर्वत पहुंचीं। उधर भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। तभी से वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कही जाती हैं।

कैसे पहुंचे - मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीसैलम में मौजूद है। आप सड़क, रेल और हवाई यात्रा के जरिए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। सड़क के जरिए श्रीसैलम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। विजयवाड़ा, तिरुपति, अनंतपुर, हैदराबाद और महबूबनगर से नियमित रूप से श्रीसैलम के लिए सरकारी और निजी बसें चलाई जाती हैं। श्रीसैलम से 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैदराबाद का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। यहां से आप बस या फिर टैक्सी के जरिए मल्लिकार्जुन पहुंच सकते हैं। यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन मर्कापुर रोड है जो श्रीसैलम से 62 किलोमीटर की दूरी पर है।

एतिहासिक जंगेश्वर मंदिर

प्राचीन व एतिहासिक शिव मंदिरों में से एक पलवल के जंगेश्वर मंदिर में श्रावण माह में हर सोमवार को हजारों श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर की मान्यता दूर-दूर तक है। पुराने शहर में स्थापित यह मंदिर लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र माना जाता है। पड़वा से पूनो तक श्रावण माह में विशेष पूजा अर्चना की जाती है।

पौराणिक व एतिहासिक महत्व

मंदिर का पौराणिक व एतिहासिक महत्व है। यह इसके नाम से ही पता लगता है। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। पहले इस मंदिर को विधर्मियों ने तोड़कर इसके ऊपर अन्य निर्माण कर दिए थे। फिर इसे काफी संघर्ष के बाद हासिल किया गया। खुदाई की गई तो प्राचीन शिवालय निकला। सन् 1802 में इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया।

मूर्ति व मंदिर के निर्माण की विशेषता

मंदिर में स्थापित शिवलिंग पत्थर का है। मौजूदा लोगों में से किसी को नहीं मालूम कि यह कितना पुराना है। मंदिर के पुजारी राम कुमार बताते हैं कि यह कुदरती है। इस शिवालय का मुख्य मुख पूर्व की तरफ है। जबकि इसके दो अन्य दरवाजे पश्चिम व दक्षिण की तरफ खुलते हैं।

मंदिर की स्थापत्य शैली

जंगेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली अन्य शिव मंदिरों की तरह ही है। इसका निर्माण कखैया ईटों व व चूने से किया गया है। बाद का सारा निर्माण बड़ी ईटों व सीमेंट का है। मंदिर की दीवारों पर देवी-देवताओं के चित्र बने हुए हैं।

पूजा, दिनचर्या, सामग्री व आराधना

मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना होती है। रोजाना सैकड़ों लोग पूजा अर्चना करते हैं। श्रावण माह में यह संख्या हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर में मेले का सा माहौल रहता है। सोमवार को विशेष श्रृंगार किया जाता है। बेल पत्र, आक, धतूरे शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। पलवल से बाहर के श्रद्धालु भी पूजा अर्चना के लिए आते हैं।

श्रावण माह में प्रतिदिन शाम को दूध-दही, गंगाजल, शहद आदि से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। हर सोमवार को फूल बंगला सजाया जाता है। ठंडाई व खीर का प्रसाद बांटा जाता है। अब पुराना मंदिर तोड़कर नया मंदिर बनाया गया है। उनके अनुसार शिवलिंग पृथ्वी से निकलकर अपने आप स्थापित हुआ।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मानसून सत्र में फिर गरमाया सरना धर्म कोड का मुद्दा

रांची। नई दिल्ली के संसद भवन में सोमवार को मानसून सत्र शुरू हुआ। इस दौरान एक फिर सदन के बाहर सरना धर्म कोड का मुद्दा गरमा गया है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने अविलंब सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। वह अपने एक तख्ता लिये हुए हैं, जिसमें जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू करने की बात कही गयी है। वह इससे पहले भी पार्लियामेंट के विशेष सत्र में भी सरना धर्म कोड की मांग उठा चुके हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुखदेव भगत ने सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाया। वे अपने साथ एक तख्ते लेकर पहुंचे थे, उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग करते हुए अविलंब इसे लागू करने की मांग की थी। उन्होंने अपने तख्ते में जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू करने की बात लिखी थी। उनके हाथ में एक दूसरा तख्ता भी था। जिसमें लिखा था आदिवासी प्रकृति पुजारी है। इनकी आस्था, परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए सरना धर्म जनगणना में शामिल करो।

सपा के पीडीए को हथियाने के लिए कांग्रेस चलायेगी अभियान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर अपनी नजर लगाए बैठे गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान एक और समाजवादी पार्टी का साथ लेकर यूपी में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है, वहीं दूसरी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने से भी नहीं चूक रही है। सपा प्रमुख जिस प्रकार मुस्लिम वोटों और जातीय जनगणना की मांग को लेकर लगातार एग्रेसिव रहते हैं, उसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिये कांग्रेस जाति आधारित गणना और पसमांदा मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे के सहारे पैठ बनाने के लिए अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस अब किसी भी वर्ग को अपने साथ जोड़ने में पीछे नहीं रहना चाहती है।

ममता ने बांग्लादेशियों को आश्रय देने की बात कही

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में संकट में फंसे लोगों को आश्रय देने की पेशकश की है। पहले ही बांग्लादेशियों की घुसपैठ से देश परेशान है। यह घुसपैठिये कई क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। यह घुसपैठिये कई जगह जनसंख्या का सामाजिक धार्मिक अनुपात बिगाड़ने में लगे हुए हैं। फिर भी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए विख्यात तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेशियों को आने का निमंत्रण दे रही है। देखा जाये तो पश्चिम बंगाल सरकार को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये मामले केंद्र सरकार द्वारा देखे जाते हैं ऐसे में ममता बनर्जी की टिप्पणियां पूरी तरह से अनुतिच हैं। हम आपको बता दें कि कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा था कि वह पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी।

बिहार में गुंडा और माफियाओं का राज : राबड़ी देवी

पटना। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। बिहार में गुंडा राज, माफिया राज है। दरअसल, सोमवार से बिहार में मानसून सत्र शुरू हुआ। राबड़ी देवी ने बिहार विधान परिषद के सभापति पद के लिए अवधेश नारायण सिंह का समर्थन किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि आज सदन का पहला दिन है और अपराध पर आगे बोलेंगी। दरअसल राजद का दावा है कि बिहार में भगवान भरोसे राज चल रहा है। राजद का साफ तौर पर कहना है कि हत्या ही हत्या! अपराध ही अपराध! किस मुँह से करते हैं ये एनडीए वाले बिहार में सुशासन की बात? इससे पहले बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में इंडिया गठबंधन द्वारा प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को शनिवार को राज्य विधान परिषद में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया।

नाम लिखने के विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

लखनऊ। कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाले ढाबों व दुकानों पर नाम लिखने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि दुकानों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इस मामले यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यात्रा मार्ग की दुकानों व ढाबों पर नाम लिखने के आदेश से अल्पसंख्यकों की पहचान उजागर करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। जो एक चिंताजनक स्थिति है।

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत, गारंटियों को पूरा करने वाला बजट पेश करेंगे: मोदी

नईदिल्ली। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। इस सत्र के दौरान मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। संसद में सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया उसके बाद मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से देश को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बार का बजट लोक लुभावन होगा और इसमें रोजगार सृजन पर विशेष जोर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के सार्थक रहने की उम्मीद जताई है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नजर संसद पर है और हमारा जोर गारंटियों को पूरा करने पर रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। यह एक सकारात्मक सत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार चुन कर आई है। उन्होंने कहा कि जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली अब देश के लिए लड़ाई लड़नी है।

हम आपको यह भी बता दें कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। सत्र के दौरान विपक्ष 'नीट' पेपरलीक और रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठायेगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का मुद्दा भी संसद में उठाये जाने की तैयारी है। सरकार ने रविवार को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया था कि वह जनहित के मुद्दे प्रभावी तरीके से उठायेगा। वैसे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की असली चुनौती आज से ही शुरू हुई है क्योंकि अब भाजपा के पास लोकसभा और राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं हैं इसलिए उसे विधेयक पारित कराने में एनडीए के सहयोगी दलों के अलावा इंडिया गठंबधन से अलग विपक्षी दलों के साथ की भी जरूरत पड़

सकती है। भाजपा के लिए मुश्किल यह भी है कि बीजू जनता दल अब पहले की तरह सहयोग नहीं कर रहा। पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक ने अपने सांसदों से प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने को कहा है।

हम आपको बता दें कि आज से शुरू हुआ मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार की ओर से छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिनमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इस सत्र में जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी। इस केंद्रशासित प्रदेश में फिलहाल विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और केंद्र का शासन है। इस सत्र में वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। लोकसभा बुलेटिन में कहा गया था कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और तालमेल लाना है। इसके अलावा, भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने की खातिर 1934 के विमान अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। सत्र के दौरान पेश और पारित किए जाने वाले अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।

बजट में आम आदमी को क्या मिलेगा ऐसा होगा मोदी 3.0 का पहला बजट

23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बचट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट से पहले ही सारी तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि हम जो बजट पेश करेंगे, वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है।

हमें पांच साल का जो अवसर मिला है, ये बजट ?हमारे उन पांच साल की दिशा तय करेगा। ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा। हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8 प्रतिशत ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई संसद के गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का आदेश किया उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहता हूं कि गत जनवरी से लेकर अब तक हमें जितना संघर्ष करना था। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है।

मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए खुद को समर्पित करें और संसद के इस गरिमामय मंच का अगले 4.5 साल तक उपयोग करें। जनवरी 2029 के चुनावी साल में आप कोई भी खेल खेल लें, लेकिन तब तक हमें किसानों, युवाओं और देश के सशक्तिकरण के लिए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना फैसला

■ **आरएसएस में अब शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, विपक्ष ने उठाए सवाल**

नईदिल्ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले हफ्ते एक आदेश जारी कर आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी अधिकारियों की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। सरकार के इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहा है। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी आदेश का एक स्क्रीनशॉट साझा किया और कहा कि 58 साल पहले जारी एक असंवैधानिक निर्देश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। वही,

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी 9 जुलाई को एक कार्यालय ज्ञापन साझा किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कानून तोड़कर जो हो रहा था वह अब नियमित हो गया है क्योंकि जी2 और आरएसएस के बीच तनाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 4 जून, 2024 के बाद, स्व-अभिषिक्त गैर-जैविक प्रधान मंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। 9 जुलाई, 2024 को, 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो वाजपेयी के प्रधान मंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। पवन खेड़ा ने कहा कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी सरकार ने आदेश वापस ले लिया है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन औवेसी ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल और नेहरू की सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें इस बात पर सहमत होना पड़ा कि वे भारतीय संविधान का सम्मान करेंगे।

लोससभा में राहुल-अखिलेश के सवाल पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा

नईदिल्ली। सोमवार को मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए है। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में सरकार जमकर घेरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर सवाल पूछे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर प्रधान की आलोचना की और कहा कि उन्होंने अब तक पेपर लीक मामले पर खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है।

राहुल ने कहा कि यह पूरे देश के सामने

स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में न केवल नीट बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में बहुत गंभीर समस्या है। मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने खुद को छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहराया है। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि वह यहां जो कुछ चल रहा है उसके बुनियादी सिद्धांतों को समझता है। नेता प्रतिपक्ष ने पेपर लीक के कारण प्रभावित छात्रों की चिंताओं को उठाया और कहा कि वे आश्वस्त हैं कि देश की परीक्षा प्रणाली धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के लोग अब मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, तो वह परीक्षा प्रणाली खरीद सकता है। अखिलेश यादव ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी ये सरकार। कुछ सेंटर तो ऐसे हैं जहां 2000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। जब तक ये मंत्री (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी की धोखाधड़ी वाली टिप्पणी को लेकर उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि यह निंदनीय है। उन्होंने कहा, सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 241 रन हराया

ट्रेंट ब्रिज। इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 241 रन से मसल दिया। तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे हो गया। तीसरा मैच 26 जुलाई से खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 385 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन चौथे दिन 23 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 143 रन पर सिमट गई। 20 वर्षीय ऑफ स्पिनर शोएब बशीर ने 41 रन देकर 5 विकेट झटके। इससे पहले, जो रूट (122) और हैरी ब्रूक (109) की यॉर्कशायर जोड़ी ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 425 रन बनाए। इंग्लैंड के 416 के जवाब में इंडीज ने पहली पारी में 457 रन बनाकर 41 रन की बढ़त ली थी।

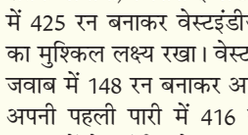

टेस्ट सीरीज में लगातार दूसरी हार के बाद वेस्टइंडीज आखिरी स्थान पर खिसक गया। 12 मैचों के बाद इंग्लैंड के पास पांच जीत, छह हार और एक ड्रॉ के साथ 31.25 प्रतिशत अंक हैं, जबकि वेस्टइंडीज के अब तक छह मैचों में एक जीत, चार हार और एक ड्रॉ के साथ 22.22 प्रतिशत अंक हैं।

जो रूट (122) और हैरी ब्रूक (109) के शतकों के बाद स्पिनर शोएब बशीर के 5 विकेट की मदद से इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 241 रन से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। रूट ने अपने करियर का 32वां जबकि ब्रूक ने पांचवा शतक लगाया, जिससे इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 425 रन बनाकर वेस्टइंडीज के सामने 385 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। वेस्टइंडीज की टीम इसके जवाब में 148 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए थे जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 457 रन बनाकर 41 रन की बढ़त हासिल की थी। बशीर ने तीन ओवर के अंदर किर्क मैकेंजी, कावेम हॉज और एलिक अथानाज़ को आउट करके वेस्टइंडीज को करारे झटके दिए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

बजट से पहले दूसरे दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 103 अंक टूटा

नईदिल्ली। बजट से पहले लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक में भारी बिकवाली के दबाव के कारण इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को निचले स्तर पर बंद हुए। इसके अलावा, ग्लोबल मार्केट में कमजोर रुख से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 102.57 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 80,502.08 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 80,100.65 और 80,800.92 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21.65 अंक या 0.09 प्रतिशत गिरकर 24,509.25 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,362.30 और 24,595.20 के रेंज में कारोबार हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में 16 शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

बजट में विकास के साथ रोजगार सृजन पर हो जोर

नईदिल्ली। अंतरिम बजट फरवरी 2024 में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था, अब जुलाई 2024 में पूर्ण केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने का समय आ गया है। 19 जून को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आगामी बजट के बारे में अपना दृष्टिकोण देने के लिए आमंत्रित किया गया। सरकारी हलकों में लोग 8 12 प्रतिशत की उच्च जीडीपी वृद्धि, 9.9 प्रतिशत की तेजी से बढ़ते विनिर्माण, अप्रैल 2024 में सीपीआई मुद्रास्फीति के 4.82 प्रतिशत के साथ मुद्रास्फीति में कमी, डब्ल्यूपीआई में कमी, राजकोषीय घाटे के बजट अनुमानों से कम रहने, रुपए में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.4% की बहुत कम दर गिरावट, और भुगतान संतुलन (बीओपी) में चालू खाता घाटा जीडीपी के बमुश्किल 0.7% रहने को लेकर उत्साहित हैं।

वित्त वर्ष 25 में 6.5-7 प्रतिशत रह सकती है जीडीपी ग्रोथ

नईदिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया। आर्थिक सर्वे 2023-24 में देश की इकोनॉमी के 2024-25 में 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया। सर्वे के अनुसार, भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर का आउटलुक उज्ज्वल रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक समीक्षा) सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा होती है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा इकोनॉमिक सर्वे तैयार की जाती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2.50 प्रतिशत से ज्यादा टूटा

नईदिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन में सोमवार को शेयर बाजार के खुलते ही दो प्रतिशत तक गिर गया। कंपनी के शेयरों में गिरावट दरअसल जून तिमाही के नतीजों में गिरावट आने की वजह से आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सोमवार को गिरावट के साथ 3070.15 रुपये के भाव पर खुला और देखते ही देखते 3019.20 रुपये प्रति शेयर तक फिसल गया। इससे पहले शुक्रवार को रिलायंस का शेयर 3109.50 रुपये पर बंद हुआ था। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 5 फीसदी की गिरावट के साथ 15,138 करोड़ रुपये पर आ गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 16,011 करोड़ रुपये था।

आम आदमी की बजट से उम्मीद!

विनीत नारायण

जहां एक तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की आर्थिक प्रगति को लेकर लगातार अपनी पीठ थपथपाती रही हैं, वहीं देश के बड़े अर्थशास्त्री, उद्योगपति और मध्यम वर्गीय व्यापारी वित्त मंत्री के बनाए पिछले बजटों से संतुष्ट नहीं हैं। अब नया बजट आने को है। पर जिन हालातों में एन.डी.ए. की सरकार आज काम कर रही है उनमें उससे किसी क्रांतिकारी बजट की आशा नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की लंबी चौड़ी वित्तीय मांगें, सत्तारूढ़ दल द्वारा आम जनता को आर्थिक सौगातें देने के वायदे और देश के विकास की जरूरत के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। वह भी तब जब भारत सरकार ने विदेशों से ऋण लेने की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आज भारत पर 205 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। ऐसे में और कितना कर्ज लिया जा सकता है? क्योंकि कर्ज को चुकाने के लिए जनता पर अतिरिक्त करों का भार डालना पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है जिसकी मार आम जनता पहले ही झेल रही है।

दक्षिण भारत के मशहूर उद्योगपति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक और आर्थिक मामलों के जानकार डा. मोहनदास पाई ने देश की मौजूदा आर्थिक हालत पर तीखी टिप्पणी की है। देश की मध्यम वर्गीय आबादी में बढ़ते हुए रोष का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि पूरे देश में मध्यम वर्ग बहुत दुखी है क्योंकि वे अधिकांश करों का भुगतान कर रहे हैं। उन्हें कोई कर कटौती नहीं मिल रही है। मुद्रास्फीति अधिक है लागत अधिक है, छात्रों की फीस बढ़ गई है व रहने की लागत बढ़ गई है। हालात में सुधार होने के बावजूद यातायात के कारण शहरों में जीवन की

गुणवत्ता खराब बनी हुई है। वे करों की दर में कमी देखना चाहते हैं। पाई उस टैक्स स्लैब नीति के पक्ष में नहीं हैं जो सरकार ने पिछले 2 बजट में पेश की है। उनके अनुसार, आयकर संग्रह 20 से 22 प्रतिशत बढ़ रहा है, इसलिए देश के मध्यम वर्ग के लिए आयकर के कई नए स्लैब और केवल आवास निर्माण के लिए कारों में छूट देने की बजाय करों में कटौती करने की आवश्यकता है।

मोहनदास पाई का तर्क केवल देश के मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारी आबादी के निचले 50 प्रतिशत हिस्से की क्रय शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास जैसी चुनौतियों पर प्राथमिक ध्यान दिया जाए। इतना ही नहीं, वे मानते हैं कि रोजगार क्षेत्र की वृद्धि को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए वे वर्तमान चुनौतियों पर काबू पाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। 80 प्रतिशत नौकरियों में 20,000 रुपए से कम वेतन मिलता है और यह एक समस्या है। वे आगे कहते हैं कि हमें कर आतंकवाद को रोकना होगा।

पाई ने प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.)पर मामलों को पूरा करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा में जवाबदेह ठहराने के लिए चार्ज शीट दाखिल करने पर ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया। उनके अनुसार 'टैक्स आतंकवाद भारत के लिए बड़ा खतरा है। चूंकि पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है, इसलिए विश्लेषकों को अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति बताने के लिए पेश किए गए आंकड़ों के पीछे जाना होगा। इसलिए, जहां स्थापित अर्थशास्त्री बजट की प्रशंसा करते हैं, वहीं आलोचक यथार्थवादी स्थिति प्रस्तुत करते हैं और इसमें वैकल्पिक व्याख्या का महत्व निहित है। यह समस्या, महत्वपूर्ण डेटा की अनुपलब्धता और इसके हेर-फेर से और बढ़ गई है। उदाहरण के लिए, जनगणना 2021 का इंतजार है। 2022 की शुरूआत के बाद महामारी समाप्त हो गई और अधिकांश देशों ने अपनी जनगणना कर ली है, लेकिन भारत में यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

जनगणना डेटा का उपयोग डेटा संग्रह के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश अन्य सर्वेक्षणों के लिए नमूना तैयार करने के लिए किया जाता है।

छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा

वर्षों से अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की बाट जोह रही जाति के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मिल कर आभार जताया

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है।

प्रदेश भर से आए पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक श्री रामकुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपुर आने के लिए

प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री साय द्वारा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22 हजार है। यूं तो ये लोग पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं।

छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसमें इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज उपस्थित जाति के लोग वास्तव में आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके हित में मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। उन्होंने समाज के सामाजिक भवन के लिए रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने नजदीक से महसूस किया है जनजातियों का दर्द- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द अच्छे से जानते हैं।

72 घंटे की मूसलाधार बारिश का भयंकर तांडव, सैकड़ों घरों में भरा पानी

रायपुर। दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से रविवार को किरंदूल में एनएमडीसी के प्रोजेक्ट 11बी के चेकडैम नंबर 6 की दीवारें ओवरफ्लो हो गईं। चेकडैम की दीवार ओवरफ्लो हो जाने से इस डैम में भरा लौह चूर्ण व पानी ऊफान की तरह नीचे उतरा। पानी व लौह चूर्ण ने अन्य पेड़- पत्थर को भी अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद यह सारा बहाव किरंदुल की तराई में बसे हुए बंगाली कैंप के सौ से अधिक घरों पर आफत बनकर टूट पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। दोपहर बाद जब हम घरों में थे एकाएक शोर करता हुआ पानी घरों में घुस आया। सभी घबरा गए। बाहर का नजारा देखा तो दिल कांप गया।

सड़कों पर पूरी रफ्तार से पानी व मलबा बह रहा था। इस जल प्रवाह में दो बच्चे, दोपहिया वाहन, कार व ट्रक जैसे भारी वाहन भी बहते नजर आए। चारों ओर चीख- पुकार का मंजर दिखाई दिया। आधे घंटे तक कुछ समझ में नहीं आया कि इतना पानी व मलबा किधर से आया। एनएमडीसी ने 11बी प्रोजक्ट के लौह चूर्ण को रोके रखने के लिए एक दस हजार क्यूबिक मीटर क्षमता वाला चेक डेम बनाया हुआ है। बारिश का पानी इस चेक डेम में भर कर रिसता हुआ बहता रहता है। तीन दिन से जारी बारिश से लौह चूर्ण भीग कर भारी हो गया व पानी का दबाव पड़ने पर इसकी दीवारें दरक गई व सारा मलबा बहता हुआ तीन सौ मीटर नीचे आने लगा। हजारों टन मलबा बंगाली कैम्प के 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड के घरों में घुस आया। बताया जा रहा है कि इस चेकडैम क्रमांक 6 की प्रत्येक साल सफाई की जाती है। बीते दो साल से इस चेक डेम की सफाई एनएमडीसी ने नहीं करवाई थी। दरअसल नगर पालिका व एनएमडीसी के बीच कतिपय विवाद की वजह से यह लापरवाही एनएमडीसी प्रबंधन ने बरती है। इसका खमियाजा यह हुआ कि क्षमता से अधिक मलबा व पानी ने बंगाली कैंप इलाको उजाड़ कर रख दिया। लोगों ने बताया कि जब यह पानी घरों में घुसा तो सभी सदस्य भीगते हुए बाहर की ओर दौड़े। इस बीच कुछ मवेशी भी बह गए। घरों में लौह चूर्ण का मलबा दो से तीन फीट तक भर गया। इससे उनके मकान के रोजमर्रा व कीमती सामान खराब हो गए। कुछ लोगों के जरुरी कागजात भी खराब हो गए। इधर यह माजरा देखकर लोग सड़कों पर जमा होने लगे हैं। देर शाम को लोगों ने यहां चक्का जाम कर दिया। लोग एनएमडीसी से इस लापरवाही के लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इस बीच एनएमडीसी के उच्चाधिकारी व अन्य ने पहुंचकर इस प्राकृतिक विपदा में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, इसके बाद चक्काजाम शिथिल किया गया। इसके बाद प्रभावितों के रहने व खाने की व्यवस्था करने एनएमडीसी जुटी हुई है।

रायपुर समेत 15 जिलों में झमाझम, मानसून फिर से सक्रिय- बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में रविवार को अतिभारी वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार 15 स्थानों पर भारी, 7 स्थान पर अति भारी और एक स्थान पर चरम अतिभारी बारिश हुई। प्रदेश में व्यापक बारिश होने का असर यह है कि अब बारिश का आंकड़ा सामान्य हो गया है। प्रदेश में 19त्न कम बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यह सामान्य माना जाता है।

कलेक्टोरेट में कॉल सेंटर प्रारम्भ, आम जनता की समस्याओं का होगा त्वरित निराकरण

बेहतर और पारदर्शी प्रशासन के मद्देनजर शुरू किया है कॉल सेंटर : कलेक्टर

रायपुर। आम नागरिकों की समस्याओं के अब त्वरित निराकरण होगा। जिला प्रशासन द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने और इसे दर्ज करने के लिए कलेक्टोरेट में कॉल सेंटर शुरू किया गया है।

कामकाज के सिलसिले में सरकारी दफ्तर में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टोरेट में बनाए गए कॉल सेंटर में दूरभाष की चार लाईनों में लोगों की शिकायतें और समस्याएं दर्ज की जाएंगी। इसके लिए 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। समस्या दर्ज होने के साथ ही लोगों के पास आएगा एसएमएस। कॉल सेंटर में दर्ज होने वाली समस्याओं के निराकरण की निगरानी के लिए एक विशेष पोर्टल भी बनाया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में पारदर्शी और बेहतर प्रशासन के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को अपने कामकाज के सिलसिले में सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। इसी सिलसिले में जिला प्रशासन द्वारा यह कॉल सेंटर शुरू किया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और बेहतर प्रशासन के मद्देनजर कलेक्टोरेट में कॉल सेंटर शुरू किया गया है। आम नागरिक राजस्व व अन्य विभागों के मामलों की जानकारी फोन कॉल के माध्यम से दे सकते हैं। जानकारी प्राप्त होने के तत्पश्चात जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा।

टेलीफोन पर दर्ज होगी समस्याएं- जिला प्रशासन द्वारा कॉल सेंटर में मोबाइल नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584, 9977222594 पर कॉल कर शिकायत दर्ज की जाएगी। दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। इस कॉल सेंटर में दिव्यांग भी अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करा सकते है। दिव्यांगों की समस्याएं वीडियो कॉल में सांकेतिक माध्यम से सुने जाएंगे।

ऐसे होगा शिकायतों का निवारण

- हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आवेदक कॉल कर अपनी समस्या शिकायत दर्ज कराएंगे।
- कॉल सेंटर की टीम शिकायतकर्ता व आवेदक से बात करती है, उनकी समस्या सुनती है और उसे कॉल सेंटर के पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
- केस दर्ज करने के बाद व्हाट्सएप के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी को मामले की जानकारी भेजी जाएगी।
- प्रकरण का त्वरित निराकरण किया जाएगा
- जब तक शिकायत का निराकरण नहीं होता, तब तक कॉल सेंटर समस्याओं पर संबंधित विभाग एवं अधिकारी से फॉलोअप करेगा।
- समस्या के निराकरण हो जाने पर आवेदक को कॉल करके सूचित किया जाएगा और पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

पीएम आवास पर भी भाजपा ने जनता को धोखा दिया

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार 18 लाख आवासों की सूची जारी करे। भाजपा सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास स्वीकृत होने का दावा किया गया था जबकि सच्चा यह है कि 18 लाख आवास में से अब तक एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है।साय सरकार गरीबो को आवास देने के नाम से धोखाधड़ी की है, जो भी आवास बने है और जो बन रहे है वो कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत हुए थे। केन्द्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधानमंत्री आवास के मकानों की संख्या को स्वीकृति ही नही दिया है। राज्य सरकार खुद ही संख्या की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवास हीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये। मोदी सरकार बताये 18 आवासों में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया? मोदी सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से 1 मकान की भी स्वीकृति नहीं दिया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के खाते में एक रू. भी नहीं डाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है.

रापुर नगर निगम के जोन कमिश्नरों का तबादला

रायपुर। राजधानी में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले जोन कमिश्नरों का तबादला हुआ है. रायपुर नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा ने इसका आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, राजधानी के जोन क्रमांक 3, 4, 7 और 8 में पदस्थ कमिश्नरों को दूसरे जोन में पदस्थापना की गई है. इसके आलावा एक उपयुक्त को जोन 8 में बतौर जोन कमिश्नर पदस्थापना दी गई है. आदेश के मुताबिक, जोन 7 आयुक्त जसदेव बाबरा को जोन 3, जोन 8 के आयुक्त अरुण ध्रुव को जोन 4, जोन 3 की आयुक्त प्रीति सिंह को जोन 7, जोन 4 के कमिश्नर राकेश शर्मा को जोन 10 में नवीन पदस्थापना दी गई है. वहीं मुख्यालय में पदस्थ त्य हालदार को उपआयुक्त पद से हटाकर जोन आयुक्त के पद में जोन क्रमांक 8 में पदस्थ किया गया है. इसके अलावा निर्वाचन एवं जनगणना का प्रभार कृष्णा खटीक उपायुक्त और जन्म-मृत्यू, विवाह पंजीयन का प्रभार स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रहण को सौपा गया है.

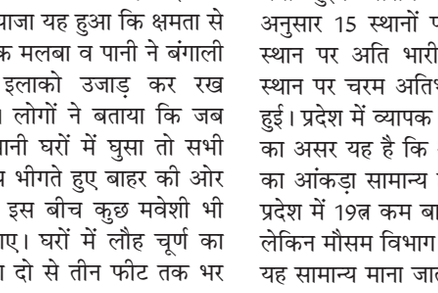

निजात अभियानः चाकूबाजी की घटनाओं में 35 प्रतिशत कमी

रायपुर। राजधानी में अवैध नशा के विरुद्ध अभियान निजात चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध

नशा और अन्य अवैधानिक कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अभियान के जनवरी माह से अब तक पिछले दो सालों की इसी अवधि की तुलना में आईपीसी के अपराधों में कमी उल्लेखनीय कमी आई है। विशेषकर चाकूबाजी में लगभग 35 फीसदी की कमी आई है। 2022 में जनवरी से 15 जुलाई के बीच 131 चाकूबाजी की घटनाएं और 2023 में इसी अवधि में 128 बार चाकूबाजी हुई। जबकि इस वर्ष जनवरी से अब तक 84 चाकूबाजी की घटना घटी है। यह कमी विजिबल पुलिसिंग, अड्डेबाजी व अपराधियों पर सख्ती के साथ निजात अभियान की कार्रवाई की वजह से है। अभियान के तहत तुलनात्मक अवधि में पिछले वर्षों से आबकारी एक्ट और ड्रग-विरोधी एनडीपीएस एक्ट के तहत 85त्न अधिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध जनजागरुकता और नशे के आदी सैकड़ों लोगों की विभिन्न संस्थाओं की मदद थानों में काउंसलिंग की जा रही है।

दुष्कर्म मामलाः आरोपी की याचिका खारिज, सजा को रखा बरकरार

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मानसिक रूप से विकलांग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के लिए आशीष सेंदरिया उर्फ भुंडू की दोषसिद्धि और 20 साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी की दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। मामले में कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय पाई जाती है तो केवल उसके आधार पर ही सजा दी जा सकती है। पीड़ित/बच्चे के मन पर घृणित कृत्य का प्रभाव जीवन भर रहेगा इसलिए सजा में छूट नहीं दी जा सकती। घटना रायगढ़ जिले की 16 अगस्त 2021 की है।

पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी ने उसकी मानसिक रूप से कमजोर बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने धारा 376 (जे) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

प्रदूषण फैलाने वाली भाटिया वाइन फैक्ट्री से 2 सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाली भाटिया वाइन फैक्ट्री से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि फैक्ट्री संचालक पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपायों की जानकारी प्रस्तुत करें। अब इस जनहित याचिका मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की गई है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस बाबत फैक्ट्री संचालक को अप्रैल में नोटिस जारी किया था,लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। बता दें कि मुंगेली जिले के मोहभट्टा स्थित शराब फैक्ट्री से प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। बीते दिनों सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया था। मामले में आबकारी, पर्यावरण के मुख्य सचिव, मुंगेली कलेक्टर, एसपी, आबकारी उपायुक्त समेत 7 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि बिलासपुर-रायपुर रोड पर मोहभट्टा में भाटिया वाइन्स का प्लांट है, जिससे निकलने वाली घटिया क्वॉलिटी की स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहा देने से बीते दिनों लाखों मछलियां मर गई।

सुकमा में ऊफान पर नदी-नाले

बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, शव को कंधे पर लादकर 20 किमी दूर गांव पहुंचे ग्रामीण

रायपुर/सुकमा। सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। भारी बारिश के बीच जिले भर से अलग-अलग तस्वीर निकलकर आ रही हैं। इन तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर आई है जहां शव को ग्रामीणों ने चारपाई के माध्यम से 20 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचे।

मामला सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित किस्टाराम इलाके के अरलापेंटा का है। जहां गंभीर बीमारी से ग्रसित एक ग्रामीण की देसी इलाज के दौरान मौत के बाद ग्रामीण के शव को इतनपाड गांव से उसके ग्रह ग्राम अरलापेंटा ले जाया जाना था, लेकिन नदी नाले उफान पर होने की वजह से शव को वाहन के जरिए नहीं ले जाया जा सका। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा यह फैसला लिया गया कि शव को चारपाई की मदद से पैदल ही 20 किलोमीटर दूर अरलापेंटा ले जाया जाए। शव को चारपाई की मदद से अरलापेंटा तक पहुंचने में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

पैसों की तंगी से अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था मरीज - गौरतलब है कि अरलापेंटा का ग्रामीण गंभीर बीमारियों से ग्रसित था और पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना के भद्राचलम के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था, लेकिन एक समय के बाद पैसों की तंगी की वजह से मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज होना पड़ा। इसके बाद बीमार ग्रामीण का इलाज बैगा के भरोसे शुरू हुआ जहां झाड़-फूंक और देसी इलाज किया जा रहा था। आखिरी वक्त में देसी इलाज भी मरीज के काम ना आया और ग्रामीण की मौत हो गई। इलाका नक्सल प्रभावित होने की वजह से जिले के 50 फ़ीसदी से अधिक इलाकों में सड़कें नहीं बन पाईं। जिस वजह से इन इलाकों के ग्रामीणों को रोजमर्रा के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से रोज दो-चार होना पड़ता है। बारिश के मौसम में इन इलाकों के ग्रामीणों को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इलाज के अभाव में यहां ग्रामीणों की मौत हो जाती है और मौत का कारण तक सामने नहीं आ पाता।

नया ट्रांसफार्मर लगने से जगमगाया रमेशपुरः ग्रामीणों में छाई खुशी की लहर

रायपुर। सूरजपुर जिले के अंतर्गत ग्राम रमेशपुर के ग्रामीणों में खुशी की लहर छाई है, क्योंकि नए ट्रांसफार्मर लगने से पूरा रमेशपुर जगमगा उठा है। वहां के ग्रामीण लगातार लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती, बार-बार ट्रांसफार्मर का खराब हो जाने जैसी समस्या से लंबे समय से परेशान थे। यहां के किसानों द्वारा धान की बुवाई हेतु लगाए गए थरहा पर्याप्त वर्षा न होने के कारण सुख जा रहा था, किसानों का कहना था कि यदि बिजली रहेगी तो हम मोटर पंप के जरिए धान के थरहा को सूखने से बचा सकते हैं। इन सभी समस्याओं से ग्रामवासियों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को अवगत कराया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने किसानों और ग्रामवासियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश के 24 घंटे के अंदर ही तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.